



04 - पड़ोसी देशों में राजनीतिक हलचल?



05 - मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सवैधानिक अधिकार

A Daily News Magazine

मोपाल  
सोमवार, 11 मई, 2026



मोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 248, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान ही माजपा की असली ताकत: हेमंत...



07 - वन स्टॉप सेंटर की संवेदनशील पहल से 85 वर्षीय महिला...

# संवाद

प्रसंगवश

## शुभेंद्रु सरकार के सामने होंगी ये बड़ी चुनौतियां

वंदन कुमार जजवाड़े

पश्चिम बंगाल में शुभेंद्रु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है।

अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में एक खास बात यह रही है कि यहाँ जिस पार्टी या गठबंधन की सरकार रही है, उसने लंबे समय तक शासन किया है। बीजेपी को अब राज्य में अपने पुराने वादों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। राज्य के लिए बीजेपी के वादों की फ्रेजरिस्ट काफी लंबी है। नए मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी के लिए ये वादे कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला है। इस विशाल बहुमत और जनता की उम्मीदों का दबाव उस पर बना रहेगा। बीजेपी को आमतौर पर हिंदी भाषी इलाकों की पार्टी के तौर पर जाना जाता है, ऐसे में उसे बांग्ला संस्कृति के साथ तालमेल बैठाकर अपने चुनावी वादों को पूरा करना होगा। वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी कहती हैं, 'बीजेपी के साथ हिन्दी पट्टी की पहचान जुड़ी है, जिसे बांग्ला पहचान के साथ तालमेल बैठाना होगा।' शुभेंद्रु अधिकारी ने जिस दिन शपथ ली वह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि रवींद्र जयंती के दिन पश्चिम बंगाल सरकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। गवर्नर के नेतृत्व में यह काम हो सकता था।

वरिष्ठ पत्रकार समीर के पुरकायस्थ कहते हैं, 'रवींद्रनाथ टैगोर से बड़ी बांग्ला संस्कृति की कोई पहचान नहीं है, वो बंगाल के लिए एक फिलोसफी है। बीजेपी को अपने सिंबोलिज्म को वास्तविकता

में बदलना होगा। बीजेपी की पहचान राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई है। महुआ चटर्जी कहती हैं, 'जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था तो नीचे जो लोग मौजूद थे, वो धार्मिक नारे लगा रहे थे, यह बंगाली नारा नहीं है। इस भावना को दिल्ली में बैठकर नहीं समझा जा सकता है।'

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार और अपराध को बड़ा मुद्दा बनाया। राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके शुभेंद्रु अधिकारी अक्सर टीएमसी के नेताओं पर संगठित अपराध में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया था। राज्य में साल 2016 में स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और चोटाले के आरोप लगे थे। करीब एक साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने करीब 25 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी। ऐसे में अब बीजेपी की सरकार आने के बाद एक स्वच्छ सरकार देना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि खुद शुभेंद्रु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहे हैं। वो 'नारदा रिटिंग वीडियो' में काम कराने के एवज में कथित तौर पर पैसे लेते देखे गए थे। इसके अलावा सारदा चिटफंड चोटाले में भी उनका नाम सामने आया था।

दरअसल साल 1998 से साल 2020 तक शुभेंद्रु अधिकारी ममता बनर्जी की टीएमसी में थे। उस समय बीजेपी ने इस रिटिंग वीडियो का इस्तेमाल टीएमसी को घेरने के लिए किया था। इसी के साथ ही राज्य में युवाओं के लिए नीकरी और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का दबाव भी सरकार पर होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने महिला सुरक्षा को

चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। खासकर साल 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के मुद्दे को शांत करने के लिए खुद ममता बनर्जी को सड़कों पर उतरना पड़ा था। ममता बनर्जी ने कथित तौर पर यह भी कहा था कि महिलाओं को रात आठ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने काफी तूल दिया और इससे महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। लेकिन इन सबके बावजूद भी ममता बनर्जी की बंगाल की जनता के बीच जमीनी पकड़ बहुत कमजोर कभी नहीं हुई।

चुनावों में ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भले ही 80 सीटें मिली हों लेकिन उनके साथ अब भी 40% से ज्यादा वोटबैंक बना हुआ है। इसके पीछे राज्य में चल रही जनकल्याण की योजनाओं का बड़ा योगदान माना जाता है। समीर के पुरकायस्थ कहते हैं, अगर बीजेपी जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने में नाकाम होती है तो वोटों की निष्ठा बदलने में ज्यादा वक़्त नहीं लगेगा।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान की बात करें तो उसने महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार और जनकल्याण की योजनाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ऐसे में उसके सामने पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहाँ आर्थिक तौर पर बड़ी संख्या में पिछड़ी आबादी रहती है, उसे हर किसी को साथ लेकर चलना होगा।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी और खासकर गृह मंत्री अमित शाह कई बार 'घुसपैठ' का मुद्दा उठा चुके हैं। यह मूल रूप से बांग्लादेश से बिना दस्तावेज के भारत आने वाले लोगों से जुड़ा मामला है। अमित

शाह इस कथित घुसपैठ को न रोक पाने के पीछे राज्य की ममता सरकार को दोषी ठहराते थे। महुआ चटर्जी कहती हैं, 'इस मामले में एक खास बात यह भी है कि जो लोग सन 1946-47 से अब तक बांग्लादेश छोड़कर पश्चिम बंगाल आए हैं, उनमें ज्यादातर हिंदू हैं। फिर हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर भारत में जो कुछ भी होगा उसकी प्रतिक्रिया पड़ोस के बांग्लादेश में देखने को मिल सकती है।'

साल 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का शासन रहा था। इससे पहले 1977 से 2000 तक ज्योति बसु और उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2011 तक पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान राज्य में कभी बड़ा सांप्रदायिक तनाव देखने को नहीं मिला है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में इस विशाल आबादी को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। खासकर पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए यह आसान नहीं होगा।

वरिष्ठ पत्रकार समीर के पुरकायस्थ कहते हैं, 'बीजेपी ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे इसके लिए अपने समर्थकों में नई सोच डालनी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा दुर्भाग्य से राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गई है। चुनाव के बाद जो भी हिंसा हुई है, उसमें कम पैमाने पर ही सही लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर रहा है।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

एमपी में 2117 किमी बनेंगी नई ग्रामीण सड़कें

## गांवों की जीवन धारा बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: मुख्यमंत्री डॉ. यादव



एमपी को पांच हजार करोड़ रुपए की सौगातें मिली

सीएम मोहन यादव ने कहा कि एमपी में अद्भुत समय चल रहा है। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के हाथों 5 हजार करोड़ की सौगातें मिली हैं। प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, देश के राज्यों के लिए अलग-अलग पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में मध्यप्रदेश को पहले के दो पुरस्कार और बाद के तीन पुरस्कार मिले हैं। मैं आज केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम और आप सदैव साथ रहेंगे। मैं वो सभी मांगें मानने की घोषणा करता हूँ, जो भी केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान अपनी लोकसभा के लिए चाहते हैं।

पूरे होने पर आज मध्यप्रदेश इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बन रहा है। इस योजना का रजत जयंती समारोह वास्तव में ग्रामीण विकास के एक नए युग का उद्घोष है। पीएमजीएसवाय-फोर और पीएम जन-मन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ देश के गांवों को मजबूत, टिकाऊ और सर्वकालिक सड़क सम्पर्क से जोड़ने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रिवरवा को सीहोर जिले के भेरूदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4 एवं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जन-मन) के कार्यों के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।



## हिमंता के हाथ में ही होगी असम की सत्ता

● चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता, बंपर जीत मिली है

दिसपुर (एजेंसी)। असम के अगले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा होंगे। उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। रिवरवा सुबह भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें हिमंता को नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सड़क पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सेनी भी मौजूद थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हिमंता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं आदरणीय मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पर भरोसा जताते हुए मुझे लगातार दूसरी बार असम की जनता के मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने

का अवसर दिया। नितिन नवीन और आदरणीय अमित शाह जी को उनके निरंतर मार्गदर्शन और दिशा-दर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं एनडीए परिवार के सभी निर्व्याज विधायकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे एनडीए विधानसभा पार्टी का नेता चुना और मुझे बलिष्ठ और सुरक्षित असम के जनादेश को पूरा करने का दायित्व सौंपा। मां कामाख्या के आशीर्वाद और असम की जनता के समर्थन से, मैं उस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हूँ जिसे हमारी पार्टी ने 2016 में शुरू किया था, ताकि मैं ए असम की सेवा में चौबीसों घंटे तैयार रह सकूँ।

तमिलनाडु के

## 'थलापति' बने विजय शपथ लेते वक़्त देने लगे स्पीच तो राज्यपाल ने टोका

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रिवरवा सुबह 10.15 बजे तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। थलापति विजय शपथ लेते समय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया है। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए सेंगोटेयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वो एस कीर्तना शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है।



मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूँ

इसके साथ ही सीएम विजय ने कहा कि मैं आपलोगों के बीच से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूँ। मैं आपलोगों के बीच से आपके परिवार के सदस्य और भाई की तरह आया हूँ। आप सभी ने मुझे सिनेमा में प्यार से अपनाया और एक बड़ा मुकाम दिया है।

सीएम विजय ने पहले ही भाषण में इरादे किए साफ

शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु के लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि यह एक नई शुरुआत है। हमने धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय आधारित शासन का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकार में उनके अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होगा। सीएम विजय ने कहा कि हमारी राजनीतिक यात्रा में समर्थन के लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने मुझसे यह कहकर राजनीति में आने को कहा था कि हम आपके साथ हैं। आज आपने मुझे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना दिया है।

subhasaverenews@gmail.com  
facebook.com/subhasaverenews  
www.subhasavere.news  
twitter.com/subhasaverenews

### शहर की सुबह

चुप रहने से उस बेगैरत के अहम की तुष्टि होती है  
उचित जवाब न दे पाना मुझे विचलित करता है  
बोलना बहुत बार मेरी हार का कारण बना  
मुँह में छुरी रखने से बेहतर है छुरी सामने रखना  
चुप्पी, जिसम का चैन है मौन मन का विक्षोभ  
चुप नहीं मौन हूँ और एक शहशाह लगातार मेरी बेचैनी में शामिल है।।  
- शैलेन्द्र शरण

## पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध की कोशिश! मचा हड़कंप

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले रिवरवा को सुरक्षा एजेंसियों में उस वक़्त हड़कंप मच गया, जब उनके संभावित रूट के पास विस्फोटक सामग्री मिली। पुलिस को कर्नालीपुरा इलाके के थाथागुनी क्षेत्र में, आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले मार्ग के निकट कुछ जिलेटिन स्टिक बरामद हुईं। रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन कर दावा किया कि एचएएल क्षेत्र और आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के आसपास विस्फोट हो सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और दोनों स्थानों पर सघन तलाशी

### बेंगलुरु दौरे से पहले काफिले के रूट पर मिला विस्फोटक

अभियान शुरू किया गया। जांच के दौरान एयरपोर्ट इलाके में कोई सदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र के पास प्रधानमंत्री के रूट पर एक पुल के किनारे, कंपाउंड वॉल के पास जिलेटिन स्टिक बरामद की गईं। इसके बाद पुलिस ने कॉल करने वाले सदिग्ध को कोरमंगला के पास स्थित एक घर से हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि बरामद विस्फोटक किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे या नहीं। पीएम मोदी के दौरे को

देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि सदिग्ध पहले भी वीआईपी दौरे के दौरान इसी तरह की धमकी भरी कॉल कर चुका है और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उसे पहले भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि इस बार विस्फोटक बरामद होने के कारण मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह किसी बड़े नेटवर्क या आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी किसी रजिशा का हिस्सा है।





## संक्षिप्त समाचार

## आईएसआई से जुड़े एमपी के 3 युवक गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस का खुलासा- मंदिर, ढाबा और मिलिट्री कैम्प उड़ाने वाले थे पाकिस्तान भेजी तरवीरें



भोपाल (नप्र)। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का दावा करते हुए एमपी के तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग दिल्ली का ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली-सोनौरिपत

## गैंग बस्ट ऑपरेशन 2.0 में खुलासा

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 'गैंग बस्ट ऑपरेशन 2.0' के तहत विभिन्न राज्यों से शाहजाद भुट्टी मॉड्यूल से जुड़े 9 सदिग्ध ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में जांच एजेंसियों को पता चला कि आरोपियों में से एक ने दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर की रेकी की थी। परिसर की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजी थीं। मॉड्यूल की योजना मंदिर में तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाने तथा फायरिंग कर दहशत फैलाने की थी।

आरोपियों के फोन से कई सदिग्ध ई-मेल मिले- एसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पीएस कुशवाहा के मुताबिक, तीनों ही आरोपी गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। तीनों के मोबाइल के ऑडियो, वीडियो कॉल से सदिग्ध नंबरों पर बात किए जाने, सोशल मीडिया से खास स्थानों के तस्वीरें पाकिस्तान भेजे जाने की पुष्टि हुई है। आरोपियों के मोबाइल से कई सदिग्ध ई-मेल भी मिले हैं। पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपियों को आतंकी साजिश में जोड़ने के एजेंड में क्या मिला था। तीनों की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई। तीनों दिल्ली में मजदूरी कर चुके हैं।

## केरल में नहीं सुलझ पा रहा सीएम का मुद्दा

- आपसी कलह से जूझ रही कांग्रेस, थरूर-खरगे की बैठक
- सीएम को लेकर 3 नेताओं में है जंग चरम पर पहुंची गुटबाजी



तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल में एलडीएफ के 10 साल के शासन को खत्म करने के बाद कांग्रेस के भीतर जर्न के बजाय गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए तीन मुख्य दावेदार वीडी सतीसन, रमेश चेत्रिथला और केशी वेणुगोपाल मैदान में हैं। शनिवार को ये सभी नेता दिल्ली में मौजूद रहे और माना जा रहा है कि अगले 24 घंटों के भीतर अंतिम नाम की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद की यह जंग अब सार्वजनिक हो गई है। तिरुवनंतपुरम से लेकर इडुक्की तक समर्थकों ने अपने-अपने नेताओं के पोस्टर और होर्डिंग्स लगा दिए हैं। सबसे विवादित घटना तब हुई जब दिवंगत नेता ओमान चांडी और केशी वेणुगोपाल की तस्वीर वाले एक

## मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार

वीडी सतीसन को विपक्ष के नेता के रूप में एलडीएफ के खिलाफ आक्रामक चेहरा माना गया। यूडीएफ का समर्थन उन्हें प्राप्त है। पूर्व विपक्ष के नेता और संगठन पर मजबूत पकड़। सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। 2021 की हार उनके नेतृत्व में हुई थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेहद भरोसेमंद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं।

फ्लेक्स बोर्ड को फाड़ दिया गया और उस पर काला तेल डाल दिया गया। कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन और पीजे कुरियन ने इस व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दबाव की राजनीति से मुख्यमंत्री तय नहीं किया जा सकता।

## ● एनसीआरबी ने जारी किए डराने वाले आंकड़े, भय का माहौल

## अचानक जान गंवा रहे भारतीय युवा, हर घंटे 120 की जा रही जान

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय युवाओं को लेकर एक चिंताजनक बात साझा की है। डाटा के मुताबिक, भारत में काम काजी युवाओं को अचानक होती मृत्यु में लगातार तेजी देखी जा रही है। 30 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के पुरुषों के बीच में ऐसी स्थिति ज्यादा बढ़ रही है। पिछले दशक से तुलना करें, तो 2017 में 23,396 युवा अचानक मौत के मुंह में समा गए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 42,688 रहा। एनसीआरबी ने अपने डाटा में अचानक मौतों में उन स्थितियों को शामिल किया है, जिसमें हिंसा को



छोड़कर बाकी अन्य में तुरंत ही या कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। इसमें हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना और अन्य स्थितियां शामिल हैं।

## सड़क हादसों में अमी भी जान गंवा रहे भारतीय

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक के अलावा सड़क दुर्घटना आज भी युवा भारतीयों की जान लेने के मामले में सबसे आगे है। 2017 में भारत में हुई सभी अचानक मौतों में 45.1 फीसदी सड़क दुर्घटना की वजह से हुई थी। वहीं 2024 में भी यह अचानक हुई मौतों में 43 फीसदी हिस्सा रोज एक्सिडेंट्स का ही है। सड़क परिवहन मंत्रालय लगातार इसको लेकर गाइडलाइंस जारी करता रहा है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है।

## अब दक्षिण के राज्यों पर बीजेपी की है नजर

नई दिल्ली (एजेंसी)। अरब सागर के तट से वर्ष 1980 में शुरू हुई भाजपा की राजनीतिक यात्रा 46 साल बाद गंगासागर तक पहुंच गई है। हालांकि, हिंद महासागर की सीमाई राज्यों तक पहुंचना अभी बाकी है। पार्टी का अगले एक दशक का लक्ष्य सारी समुद्री सीमाओं वाले प्रदेशों में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाना है। इसके लिए अब पार्टी अपने मिशन दक्षिण के लिए बदली हुई रणनीति पर काम करेगी। भाजपा की पहुंच से दूर रहा तेलंगाना उसका पहला लक्ष्य है। उसके बाद केरल और तमिलनाडु की व्यूह रचना पर काम होगा। कर्नाटक में उसे अगले ही चुनाव में वापसी की उम्मीद है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही अमित शाह ने भाजपा की कमान संभाली थी। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में भाजपा के पूर्वोत्तर विस्तार और कोरोमंडल में पहुंच का विशाल रोड मैप पेश किया था। पूर्वोत्तर से कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने और प्रमुख पूर्वी राज्यों बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में अपने मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब वह अग्ररे मिशन दक्षिण की ओर बढ़ने जा रही है।

## तमिलनाडु में अपना एंगी बंगाल वाला फॉर्मूला



## वाम दलों की जगह लेने की तैयारी

केरल भाजपा से ज्यादा आरएसएस की मजबूती के लिए जाना जाता है। इस बार के चुनाव में भाजपा ने बदलाव वाले चुनाव में अपने लिए तीन सीट जीतकर तथा पांच सीट पर दूसरे स्थान पर रहकर अपने भावी अभियान की शुरुआत कर दी है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा वाम दलों की हार के बाद अब उसका स्थान खुद हासिल करने की तैयारी में है। राज्यों में हिंदू समुदाय की सालों से पसंद रहे वाम दलों की जगह अब भाजपा लेने की तैयारी में है। ईसाई समुदाय में भी भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई है।

## तमिलनाडु में तैयार भाजपा की जमीन

दक्षिण के पांच राज्यों में भाजपा अभी आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम के साथ गठबंधन सरकार में है। कर्नाटक में कई बार सरकार बना चुकी पार्टी को अगले चुनाव में फिर से सत्ता में आने का भरोसा है। बाकी तीन राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु एवं केरल उसके अगले लक्ष्य हैं। तेलंगाना में भाजपा की जमीन तैयार हो चुकी है। केरल और तमिलनाडु ही उसके लिए सबसे मुश्किल राज्यों में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल का फॉर्मूला अपनाएगी और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अनाद्रमुक के कई प्रमुख नेताओं को अपने साथ लाएगी। यहां हाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने नागेंद्र भी अनाद्रमुक से ही आए हैं।

## प्रदेश में सभी तरह के उद्योगों की स्थापना पर जोर, युवाओं के लिए रोजगार प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

## मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी है विकास को रफ्तार: प्रणव अदाणी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सभी तरह के उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए सक्रिय है। पर्यटन और पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करेगा। गुना क्षेत्र में सीमेंट निर्माण इकाई से डेढ़ हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अडाणी समूह की ओर से 32 हेक्टेयर भूमि पर इस इकाई की स्थापना के फलस्वरूप 4 मिलीयन टन सीमेंट उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-



पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों से गुना जिले में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा आमजन को बेहतर सेवाओं का लाभ मिलेगा। प्रदेश का ग्वालियर और चंबल अंचल कभी डकैतों की गोलियों से गुंजाता था, अब यहां विकास का परचम लहरा रहा है। अब यहां दस्युओं के स्थान पर प्रगति पहचान का माध्यम बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है।

## बीजेपी को रोकने के लिए वाम के साथ भी जाने को तैयार

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में कभी वामपंथ की सबसे बड़ी विरोधी मानी जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर अब विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बदलते नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रिमो ने भाजपा को रोकने के इराते से विपक्षी दलों से साथ आने की अपील की है। ममता ने संकेत दिए हैं कि भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उन्हें वामदलों और यहां तक कि धुर-वामपंथियों से भी परहेज नहीं है। उनका यह बयान न केवल बंगाल बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। जिस ममता बनर्जी ने तीन दशक पुराने वामपंथी किले को ढहाया था, आज वही उनके साथ मंच साझा करने की बात कह रही हैं। ममता बनर्जी की राजनीति की नींव ही वामपंथ के विरोध पर टिकी थी। 1970 और 80 के दशक में जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा अभेद्य माना जाता था, तब ममता बनर्जी एक आक्रामक युवा नेता के रूप में उभरीं।

## आज की मजबूरी या आगे की रणनीति

पिछले एक दशक में बंगाल की राजनीतिक जमीन पूरी तरह बदल चुकी है। वामदल हाशिए पर चले गए हैं और भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। ममता बनर्जी अब महसूस कर रही हैं कि मतों का बिखराव अंततः भाजपा को फायदा पहुंचाता है। हालिया बयानों में ममता ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से बंगाल में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष की एकता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि देश को बचाना है और धर्मनिरपेक्षता को कायम रखना है तो सभी गैर-भाजपाई ताकतों को एक साथ आना होगा। इसमें उन्होंने विशेष रूप से वाम और घोर वामपंथी विचारधारा वाले समूहों का नाम लेकर सबको चौंका दिया है।

## कांग्रेस धोखेबाज, डीएमके की पीठ में घोंपा छुरा

## कर्नाटक में 'आर्ट ऑफ लिविंग' के प्रोग्राम में बोले मोदी

बेंगलुरु (एजेंसी)। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- कांग्रेस और डीएमके के बीच पिछले 25-30 साल से करीबी संबंध रहे हैं। डीएमके ने कई बार कांग्रेस को संकट से बाहर निकाला। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक चली कांग्रेस सरकार भी डीएमके के समर्थन की वजह से ही टिकी रही। डीएमके ने हर समय



कांग्रेस के हित में काम किया, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके

## बेंगलुरु में पीएम के कार्यक्रम स्थल से 3 किमी दूर मिली जिलेटिन छड़े

कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा जांच के दौरान दो जिलेटिन छड़े बरामद हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, ये मुख्य कार्यक्रम स्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर फुटपाथ के किनारे मिलीं। एसीपी सेंट्रल रेंज बेंगलुरु ने बताया कि शुक्रवार सुबह पीएम मोदी के पहुंचने से पहले इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान दो जिलेटिन छड़े बरामद की गईं। फिलहाल मामलों की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि छड़े कैसे पहुंचीं।

## 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली

पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत पा रही पीएम ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 40 साल पहले 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी पिछले तीन चुनावों में मिलकर भी 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का अहंकार इतना ज्यादा है कि वे अपनी हार के लिए पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीएम ने बीजेपी और एनडीए की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में पार्टी को बड़ा समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार और असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को पहली बार इतना बड़ा जनादेश मिला है। उन्होंने इसे पार्टी के लिए अहम राजनीतिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा यह भी कहा कि दो हफ्ते पहले गुजरात में हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। उनका मुताबिक, गुजरात बीजेपी ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।

## बंगाल की करारी हार से बदले ममता के तेवर

## सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से बनाई पहचान

साल 2006-2008 के दौरान सिंगूर में टाटा नेनो प्लांट के खिलाफ भूमि अधिग्रहण आंदोलन और नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग की घटनाओं ने ममता बनर्जी को बंगाल की जनमानस का मसीहा बना दिया। उन्होंने 'मां, माटी, मानुष' का नारा दिया, जिसने वामपंथ के उस सर्वहारा वर्ग को अपनी ओर खींच लिया जो कभी माकपा का आधार था। साल 2011 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। बुद्धदेव भट्टाचार्य की हार और राइटर्स बिल्डिंग से लाल झंडे का हटना भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। उस समय ममता ने कसम खाई थी कि वह बंगाल से वामपंथ का नामोनिशान मिटा देंगी।



## जमीनी कार्यकर्ताओं का टकराव

बंगाल के गांवों में आज भी टीएमसी और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है। क्या शीर्ष नेतृत्व के हथ मिलाने से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता एक-दूसरे को स्वीकार करेंगे। वामदलों के लिए ममता बनर्जी आज भी उनकी सत्ता छीनने वाली नेता हैं। माकपा के कई नेता ममता पर ही भाजपा को बंगाल में जगह देने का आरोप लगाते रहे हैं। धुर-वामपंथी समूह अक्सर संसदीय राजनीति से दूरी बनाकर रखते हैं या बेहद कट्टर रख अपनाते हैं। ममता का उन्हें साथ आने का न्योता देना यह दर्शाता है कि वह भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ममता बनर्जी का यह हृदय परिवर्तन राजनीति की उस कड़वी सच्चाई को दर्शाता है।

## परिष्कार

## भाजपा मध्यप्रदेश में युवा एवं जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में



अरुण पटेल

लेखक  
सुबह सवेरे के  
प्रबंध संपादक हैं

मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भाजपा युवा नेतृत्व व नये चेहरों को मौका देती नजर आ रही है ताकि जमीनी स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन का एहसास हो सके। यही कारण है कि उपयुक्त और जीतने योग्य उम्मीदवारों की खोजबीन का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दिया है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब उन लोगों की टिकटों पर कैची चल सकती है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और लगातार तीन बार पार्षद रह चुके हैं। इनमें से उसे ही अपवाद स्वरूप टिकट मिल सकती है जिसका कोई उचित जीतने योग्य विकल्प पार्टी को न मिले। चूँकि संचार और लोगों तक पहुंचने के संसाधन बदल रहे हैं तथा हर व्यक्ति के पाकेट में मोबाइल के रूप में चलता-फिरता संसार समाया हुआ है और वह उसमें देख सकता है कि कौन कितना सक्रिय है। ऐसा समझा जाता है कि इंटरनेट मीडिया पर उम्मीदवारों की सक्रियता और उनके समर्थकों की संख्या व डिजिटल जुड़ाव को प्रत्याशी चयन का अहम आधार बनाया गया है। अगले वर्ष यानी 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं और यदि यह चुनाव समय पर होते हैं तो फिर अभी से चुनावी नगाड़े शनैः-शनैः बजने लगेंगे जो धीरे-धीरे तेज होते जायेंगे। इससे पूर्व जब नगर निगम के चुनाव हुए थे उस समय 16 नगर निगमों में से 5 में कांग्रेस और एक में आम आदमी पार्टी का महापौर चुना गया था। इसके अतिरिक्त अन्य

नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में भाजपा का दबदबा साफ-साफ नजर आ रहा था। इन निकायों में अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता के स्थान पर पार्षदों के माध्यम से कराये गये थे। चूँकि मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने फिर



निर्णय बदल लिया है और अब अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा मतदान से कराया जायेगा इसलिए अब सीटों का भी आरक्षण करना होगा।

भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि चुनाव के ठीक पहले के बजाय अभी से प्रत्याशी तय करने की दिशा में काम किया जाये। संगठन के फीडबैक के आधार पर संभावित प्रत्याशी को लेकर सर्वे भी कराया जायेगा। भाजपा के संभागीय और

जिला प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गयी है कि वे अपने-अपने प्रभार के क्षेत्र में ऐसे युवाओं को चिन्हित करें जो पार्टी में सक्रिय व लोकप्रिय हों, ऐसे युवाओं के नाम ही आगे बढ़ाये जायेंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपना दबदबा राजनीति



में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण दिया है ताकि वह जो कदम सभी वर्गों के कल्याण के लिए उठा रहे हैं उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया जा सके। संदीपनी विद्यालय डॉ. यादव का एक पसंदीदा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको देखने के लिए ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्यप्रदेश में आने का न्यौता दिया है। उन्हें यह आश्वासन मिला है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री

धर्मेन्द्र प्रधान भी मध्यप्रदेश आयेंगे। धर्मेन्द्र प्रधान जून माह के पहले पखवाड़े में आ सकते हैं। चूँकि मध्यप्रदेश में केंद्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले लागू हुई है इसलिए डॉ. यादव चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मध्यप्रदेश आयें, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनके



द्वारा स्थापित संदीपनी विद्यालय पूरे देश के लिए मॉडल बनेंगे।

### बंगाल में खिला कमल और दक्षिण में जोर मारता पंजा

चुनावी नतीजे सामने आ गये हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव की व्यूहरचना बनाती है और आगे बढ़ रही है उसी तरह दक्षिण

भारत के कुछ राज्यों में पंजा अपना जोर दिखा रहा है। भले ही इससे उसके पुराने सहयोगी नाराज हो जायें लेकिन कांग्रेस फिलहाल तामिलनाडु में सत्ता में भागीदारी करने जा रही है तो वहीं केरल में उसका अपना प्रभाव साफ नजर आ रहा है तथा अपने सहयोगियों के साथ उसने केरल में विजय हासिल कर ली है। आने वाले कुछ माहों में ही पता चल सकेगा कि सत्ता की यह भागीदारी कांग्रेस के लिए जोखिमपूर्ण रही या नहीं। मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव अगले वर्ष होंगे लेकिन भाजपा ने अभी से फूक-फूक कर कदम रखने चालू कर दिये हैं, देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस इसके उत्तर में क्या करती है।

### और यह भी

नगरपालिका पार्षद से 31 साल पहले अपना राजनीतिक सफर तय करते हुए आखिरकार 56 साल के सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में सफल रहे हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री रहे तो उनके दो भाई दिवेंदु और सामेंदु भी सांसद रहे हैं। वामपंथियों का शासन उखाड़कर फेंकने वाले नंदीग्राम आंदोलन के अगुवा सुवेंदु ही थे, लेकिन ममता बनर्जी से मतभेद गहराने के कारण वे भाजपा में शामिल हो गये और अंततः पश्चिम बंगाल के सत्तारोष पर पहुंचने में सफल रहे।

## हम सबके जीवन का मूल आधार है मां : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मातृ दिवस पर मातृ शक्ति को किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मातृ दिवस पर प्रदेश की सभी मातृ शक्ति को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि मां हम सभी के जीवन का मूल आधार है। मां हमें संस्कार और सत्य एवं संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हम सभी पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी मंगलकामनाएं की हैं।

## वया राजनीतिक रसूख कानून से बड़ा हो गया है? : संगीता शर्मा

भोपाल। मध्यप्रदेश में महिला न्याय को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 29 अप्रैल को राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से मामला गरमा गया है। मातृ दिवस के अवसर पर इस मुद्दे ने और अधिक संवेदनशील रूप ले लिया है, जहां एक पॉइंट महिला को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व सदस्य मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग सुश्री संगीता शर्मा ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय पर महिलाओं के साथ कथित अशोभनीय व्यवहार, यौन शोषण, पद के दुरुपयोग एवं अन्य आपराधिक कृत्यों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में की गई शिकायतों पर भी प्रभाव के चलते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।

कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व सदस्य मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग सुश्री शर्मा ने कहा है कि 29 अप्रैल को विधिवत ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट प्रगति या जांच की स्थिति सामने नहीं आई है, जिससे पॉइंट पक्ष में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करते हुए दोष सिद्ध होने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई एवं संबंधित विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की बात दोहराई है।

इसके अतिरिक्त एक वृद्ध महिला की संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे का मामला भी उठाया गया है, जिसे कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया गया है।

मातृ दिवस के संदर्भ में संगीता शर्मा ने कहा है कि यदि एक पॉइंट को न्याय नहीं मिल पाता, तो महिला सम्मान के दावे खोखले साबित होते हैं। सुश्री शर्मा ने महामहिम राज्यपाल महोदय और शासन-प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।

## मेपकॉस्ट में आज मनेगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

भोपाल। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल द्वारा इस वर्ष भी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन परिषद मुख्यालय के मुख्य सभागार में किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर भोपाल शहर के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित 27 शिक्षण संस्थानों के 250 से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षकगण सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार तथा तकनीकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। आयोजन के अंतर्गत डॉ. राजीव अग्रवाल, उद्योगपति, लाइफ कोच, मेंटर एवं मोटिवेशनल गुरु तथा डॉ. विजय भास्कर सेमवाल, सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें आधुनिक तकनीकों, नवाचार तथा राष्ट्र निर्माण में विज्ञान की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान रोबोटिक्स पर एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अर्पित सोनी, निदेशक, रोबोनोंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रतिभागियों को रोबोटिक्स एवं आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोगों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की जाएगी। इस कार्यशाला में विद्यार्थी टीमों के माध्यम से मॉडल्लस तैयार करेंगे। कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन के क्षेत्र को समझने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर परिषद के कार्यकारी निदेशक डॉ.विवेक कटार, परिषद के प्रधान वैज्ञानिक एवं विज्ञान लोकव्यापीकरण योजना के प्रभारी डॉ विकास शेंडे भी विद्यार्थियों से भारत द्वारा विकसित देशज प्रौद्योगिकी के बारे में संवाद करेंगे।

# भोपाल में बेतवा नदी को पुनर्जीवित करने की पहल

झिरी में उद्गम स्थल पर जुटे लोग, कहा-यहां से कुरवाई तक चलेगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पास ग्राम झिरी स्थित बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने और नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए रविवार से पहल शुरू हो गई। यहां पर बड़ी संख्या में भोपाल, इंदौर के रिटायर्ड अफसर और एकस्पर्ट जुटे। बेतवा अध्ययन एवं जनजागरण रूप के बैनरतले पुनर्जीवित करने के लिए मंथन किया।

मप्र-छत्तीसगढ़ के पूर्व आयकर आयुक्त आरके पालीवाल के नेतृत्व में रविवार को बेतवा उद्गम स्थल कोलार डेम के नजदीक बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि भोपाल से कुरवाई तक नदी में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

जनभागीदारी से बीते साल 55 चैक डेम बनाए गए थे। इस बार वन समितियां भी जुड़ गई हैं। वहीं, वन विभाग के कई रिटायर्ड अफसर जुड़े हैं। इसलिए उद्गम से ऊपर ओर



बीते साल से अधिक चैक डेम बनाए जाएंगे। इस मुहिम में मप्र हाईकोर्ट से जल संरक्षण के

लिए नियुक्त एडवोकेट मनीष विजयवर्गीय, डॉ सुरेश गर्ग, कई वन अधिकारी शामिल हुए।

## प्राइवेट अस्पतालों की सही रिपोर्टिंग जरूरी

तभी महामारी की सही तस्वीर सामने आएगी, सीएमएचओ बोले- अधूरी रिपोर्टिंग से बिगड़ सकते हैं फैसले



भोपाल (नप्र)। संक्रामक रोगों की समय पर पहचान, रोकथाम और संभावित आउटब्रेक से निपटने के लिए प्राइवेट अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि महामारी के पैटर्न को समझने और आउटब्रेक मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की रिपोर्टिंग अहम भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग भोपाल ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला आयोजित की। इसमें संक्रामक रोगों की निगरानी और समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए जरूरी फॉर्मेट, प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

### संक्रामक रोगों का डेटा बेहद जरूरी

डॉक्टरों ने प्राइवेट सेक्टर के रिपोर्टिंग सही ढंग से होने पर चर्चा की। डॉक्टरों ने प्राइवेट सेक्टर के रिपोर्टिंग सही ढंग से होने पर चर्चा की।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ मनीष शर्मा ने कहा कि भोपाल जैसे बड़े शहरों में शासकीय संस्थानों के साथ-साथ निजी स्वास्थ्य संस्थाएं भी बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में संक्रामक रोगों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए प्राइवेट सेक्टर से डेटा मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनमोल पोर्टल पर नियमित प्रविष्टियों की भी जानकारी साझा की।

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि बीमारियों से जुड़ी जानकारी समय पर सरकार

तक पहुंचने से संक्रमण की शुरुआती पहचान, अलर्ट जारी करने और आउटब्रेक मैनेजमेंट में तेजी आती है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों के डेटा के आधार पर उभरती महामारियों या स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सही आकलन संभव नहीं है।

### अंडर रिपोर्टिंग खतरनाक है

विशेषज्ञों ने चेताया कि अंडर रिपोर्टिंग की वजह से बीमारी के वास्तविक प्रसार का अनुमान प्रभावित हो सकता है, जिससे नीति और उपचार स्तर पर गलत निर्णय लेने का खतरा बढ़ जाता है। कार्यशाला में यह भी स्पष्ट किया गया कि नोटिफायबल डिजीज रिपोर्टिंग के कानूनी दायरे में निजी अस्पताल और हेल्थ फेसिलिटीज भी आते हैं। ऐसे में रिपोर्टिंग सिर्फ वैज्ञानिक जरूरत नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है।

## टिंबर मार्केट में आग, डेढ़ घंटे में बुझी 20 फीट तक ऊपर उठी लपटें; पीछे से गुजरती रही ट्रेनें

भोपाल (नप्र)। भोपाल शहर के बीचोंबीच टिंबर मार्केट में रविवार को फिर आग लग गई।

लकड़ी की एक दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि लपटें 20 फीट तक ऊपर उठ गईं। इसके ठीक पीछे रेलवे ट्रैक हैं। जहां से ट्रेनें गुजरती रहीं। तेज हवा की वजह से डेढ़ घंटे में आग काबू आ पाई।

आग लगने की घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। बरखेड़ी ऑटो स्टैंड के पास टिंबर दुकान में आग लग गई। धीरे-धीरे आग तेजी से फैलती गई। दमकल की मदद से उसे बुझाया जा सका।

## अर्जुन नगर से हटाई 38 झुग्गियां

### अयोध्या बायपास के 10 लेन में आड़े आ रही थीं; परिवारों की लालपुरा में शिपिटिंग

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अयोध्या बायपास को 10 लेन में बदला जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट में कई दुकानें, मकान, धार्मिक स्थल और सरकारी भवन बाधा बन रहे हैं। जिन्हें हटाया जा रहा है। रविवार को अर्जुन नगर से कुल 38 पक्की झुग्गियां हटाई गईं हैं।

यहां रह रहे परिवारों को जमुनिया ग्राम पंचायत के गांव लालपुरा में शिफ्ट किया गया है।

गोविंदपुरा एसडीएम भुवन गुप्ता ने बताया कि झुग्गी में रह रहे परिवारों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे। वहीं, शनिवार को अनाउंसमेंट भी किया था। इसके चलते कई लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान खाली कर दिए थे। बाकी को रविवार को हटाया गया।

### मई में पहली बार तेज गर्मी का दौर

प्रदेश में 30 अप्रैल से आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया था। लगातार 10 दिन यानी, 9 मई तक प्रदेश में बारिश हुई। कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) का असर देखने को मिला तो कभी चक्रवात और ट्रफ का। इस वजह से मई के पहले सप्ताह में बारिश हुई। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि 10 मई से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इससे गर्मी का असर बढ़ने लगेगा। 12-13 मई को पश्चिमी हिस्से के कुछ जिलों में लू का अलर्ट भी किया है।

## प्रदेश में अब चलेगी लू, आंधी-बारिश का दौर थमेगा

रतलाम में 44 डिग्री पर पहुंचा दिन का तापमान, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा

भोपाल (नप्र)। एमपी में अब आंधी, बारिश, ओले का दौर थमेगा और तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम केंद्र ने 12 मई से प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। रविवार से ही गर्मी असर दिखाने लगेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में एक ट्रफ और एक साइक्लोनिक स्कुलेशन (चक्रवात) की एक्टिविटी देखने को मिली। इस वजह से कई शहरों में बादल छापे रहे।

शाम को भोपाल, बैतूल, सिवनी, पांडुर्णा, डिंडीरी, अनूपपुर, रायसेन, गुना, विदिशा, राजगढ़, सागर, जबलपुर, दमोह, बालाघाट, मंडला, उमरिया, शहडोल और छिंदवाड़ा में बारिश हुई और आंधी चली।



## वार्ता

संपादकीय  
सीएम विजय: कांटों का ताज

तमिलनाडु में धूमकेतु की तरह उभरी नवोदित तमिलणा वेत्री कषघम (टीवीके) पार्टी के मुखिया जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने मुख्यखमत्री पद की शपथ लेकर सरकार तो बना ली है, लेकिन यह उनके लिए कांटों के ताज से कम नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद जारी अटकलों के दौर के बीच रिविवर को मुख्यमंत्री विजय और उनके नौ सहयोगियों ने जैसी ही पद और गोपनीयता की शपथ ली, वैसा ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शपथ लेते ही विजय ने मंच पर ही तीन अहम फैसलों का ऐलान किया। ये हैं हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल का गठन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। गौरतलब है कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके 234 में से 107 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 11 दूर रह गई। टीवीके को सबसे पहले कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के समर्थन की पेशकश की। लेकिन बाकी दल सौदेबाजी करते रहे। अंततः 4 वामपंथी, 2 वीसीके और 2 इंडियन मुस्लिम लीग के विधायकों ने समर्थन पत्र दिया, जिस के बाद राज्यापाल ने विजय को सीएम पद की शपथ दिलाई। हालांकि विजय की अनुभवहीनता और अति उत्साह शपथ ग्रहण के दौरान भी दिखा, जब राज्यापाल द्वारा शपथ दिलाना शुरू करते ही वो शपथ पढ़ने की जगह भागपा देने लगे। इस पर राज्यापाल को उन्हें टोकना पड़ा। विजय ने शपथ तो ले ली है, लेकिन उनकी असली आँख परीक्षा अब शुरू हुई है। सबसे पहले तो उन्हें 13 मई को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना है। इसको लेकर शंका का कारण है कि भले ही पांच दलों ने उन्हें समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है, लेकिन इनमें से कोई भी सरकार में शामिल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टीयों ने तो साफ कह दिया है कि वो भाजपा को रोकने के लिए विजय को समर्थन दे रही हैं। वो सरकार में शामिल नहीं होंगी। अलबत्ता कांग्रेस सरकार में शामिल होने के लिए जरूर उत्सुक है। वहीं कारण है कि रहल गंधी खुद शपथ ग्रहण में शामिल हुए। नए सीएम विजय के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक तो उन्हें लगातार समर्थन देने वाले दलों के दबाव में काम करना होगा, दूसरे उन्होंने जो लोगों से बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, उसे पूरा करना और पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का इंतजाम करना होगा। माना जा रहा है कि विजय के इन वादों को पूरा करने के लिए राज्य को 1 लाख करोड़ रु. की जरूरत होगी, जो अकेले तमिलनाडु सरकार के बस की नहीं है। समर्थक दल विजय को केन्द्र सरकार के आगे झुकने नहीं देंगे और केन्द्र सरकार कांग्रेस समर्थित सरकार को काम करने नहीं देगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने पर विजय को कंधाई दी है, लेकिन इसमें यही संदेश छिपा है कि वो कांग्रेस के बहुत करीब नहीं जाएँ। दूसरी तरफ पीएम ने विजय की शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस एक थोड़ेबाज पार्टी है। तमिलनाडु में सत्ता जाते ही उसने डीएमके को धोखा दिया। इस आरोप पर डीएमके की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन यह तय है कि विजय सरकार को एक तरफ डीएमके को दूसरी तरफ एआईडीएमके से लगातार चुनौती मिलती रहेगी। दरअसल भाजपा चाहती थी कि विजय एनडीए सदस्य एआईडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाए। इससे रूख से भाजपा का विजय सरकार पर नियंत्रण रहता और कांग्रेस भी सत्ता से बाहर रहती। लेकिन विजय के कांग्रेस के साथ जाने से सारा गणित गड़बड़ गया है।



नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

भारत के दो पड़ोसी देशों के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। दोनों जगह अलग-अलग ढंग से जेन जी याने वह युवा पीढ़ी जो 1997 या उसके बाद की है, के द्वारा सरकारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ की सरकारें भंग हुईं तथा वहीं नये चुनाव हुए। वैसे तो कुछ दिनों पूर्व श्रीलंका के भी चुनाव ऐसे ही जेन जी के आंदोलन के बाद हुए थे जिसमें काफी हिंसा और लूटपाट हुई थी और वहाँ की लंबे समय से निर्वाचित सरकार को हटना पड़ा और सेना ने नियंत्रण किया था। वहाँ एक नौजवान चुनकर आये व राष्ट्रपति बने तथा ऐसा कहा जाता है कि वे मार्क्सवादी है और चीन समर्थक है। हालांकि अभी तक उन्होंने चीनी विदेश नीति के लक्ष्यों को कम से कम जाह्रातौर पर अमल में नहीं लाया है और न ही उसके वे खिलाफ भी है। याने विचारधारा चाहे जो भी हो परंतु वे अपने देश के हितों के अनुकूल शांत तरीके से निर्णय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में उन्होंने चीनी लाइन को बाधा नहीं बनने दिया। यह उनकी समझदारी और विदेश नीति का संतुलन ही कहा जाना चाहिए।

बंगलादेश में जो इस्लामिक युवा विद्रोह हुआ था। उस समय एक चिंता भारत व अन्य देशों में उत्पन्न हुई थी कि उसके बाद बंगलादेश कहीं फिर से सैनिक तानाशाही में तो नहीं फँस जायेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना को सेना के संकेत पर देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। श्री युनुस को विदेश से वापिस बुलाकर उनको देश का कार्यभार सौंपा गया, जिसे सेना ने भी स्वीकार किया था। यह आश्चर्यजनक भी था कि युनुस को अमेरिका समर्थक माना जाता है। उन्हें एक प्रकार सेना ने स्वीकार किया, बंगलादेश के लोगों ने स्वीकार किया, उससे इतना संकेत तो मिलता ही है कि बंगलादेश की उथल पुथल की डोर कहीं न कहीं अमेरिका के पास रही है। वहाँ, इस्लामिक छात्रों ने तत्कालीन शेख हसीना की सरकार व उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू किया था। प्रधानमंत्री से लेकर अनेकों मंत्रियों को भागना पड़ा था और सेना ने भी एक प्रकार से विद्रोही इस्लामिक कट्टरपंथियों का साथ दिया था। उस समय तीन प्रकार की संभावनायें सामने आई थीं एक, श्री युनुस अंतिम कार्यभारो मुखिया थे ही उनको बंगलादेश का आगामी मुखिया बनाया जा सकता था। दूसरा, जिन कट्टरपंथी युवाओं ने वहाँ विद्रोह शुरू किया था, तब मुझे लगता है कि यह विदेशी शक्तियों द्वारा प्रयोजित था। चुनावों के बाद उनकी सत्ता आयेगी, तीसरा अनुमान था कि सेना ही सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। इन सब घटनाक्रम के पीछे चीन

## पड़ोसी देशों में राजनीतिक हलचल?

और अमेरिकन शक्तियों का अनुमति संघर्ष लगता था। शेख हसीना चीन के दौरे से लौटकर आई थीं और सत्ता पलट का खेल शुरू हो गया था। याने चीन के साथ उनका जो अंतर संबंध था वह दुनिया के चीन विरोधी समूह को स्वीकार नहीं था। बंगलादेश में भी आश्चर्यजनक रूप से उसी प्रकार सेना ने भूमिका अदा की जिस प्रकार श्रीलंका में फिर से या एक जमाने में रूस में की थी। एक अर्थ में स्थिति साफ है कि बंगलादेश की सेना कहीं न कहीं भले ही अपने आर्थिक या अन्य हितों के चलते वैश्विक शक्तियों के इशारे पर काम कर रही थी।

जिस घटनाक्रम को लेकर बंगलादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में सारे बंगलादेश में फैला। बाद में यह कट्टरपंथी इस्लामिक छात्रों व युवा नेतृत्व के पास चला गया था। इस आंदोलन की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई थी। शेख हसीना की सरकार ने बंगलादेश की मुक्ति वाहनी ( जो उनके स्वरू पिता व बंगलादेश के जनक शेख मुजीब के द्वारा बनाई गई थी) के उन परिवारजनों को जो बंगलादेश के निर्माण आंदोलन में जेलों में गये थे, यातनायें सही थीं, पाकिस्तानी जुल्म सह थे, जो विभिन्न शासकीय पदों व नीतियों में आरक्षण में वृद्धि दी, जिसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। यह बात भी सही है कि बंगलादेश के निर्माण व इस आंदोलन को आज लगभग 55 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस आंदोलन के हिस्सेदार लोग अब बहुत कम ही बचे हैं परंतु उनके परिजनों को मिल रही आरक्षण और वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध इन नौजवानों द्वारा किया था। इसको लेकर पहले मुक्ति वाहनी के समर्थक छात्रों और आरक्षण के विरोधी छात्रों के मध्य टकराव शुरू हुआ जो बढ़कर बंगलादेश में सत्ता परिवर्तन का कारण बना। कभी-कभी ऐसी कुछ घटनायें आश्चर्यजनक ढंग से होती हैं जहाँ पर छोटें से सवालें से शुरू हुए आंदोलन, कुछ ही दिनों में विशालकाय आंदोलन का रूप ले लेते हैं। 1974 में गुजरते में छात्रों का आंदोलन छात्रावास में मेस की थाली के दाम बढ़ाने से शुरू हुआ जो बाद में गुणवत्ता सरकार को भंग करने का कारण बना। फिर बिहार व देश के अनेकों इलाकों में यह आंदोलन फैला, देश में आपातकाल लगा और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा।

श्री युनुस के कार्यकाल के दौरान कट्टरपंथी युवकों के द्वारा काफी हिंसक घटनाओं के अंजाम दिया गया, विशेषतौर से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को हिंसा का शिकार बनाया गया, इस्कान को मुखिया को मारा गया, कई को गिरफ्तार किया गया और ऐसा लग रहा था कि बंगलादेश चुनाव में जनमत कट्टरपंथियों के साथ जायेगा। अब चुनाव के बाद बंगलादेश में बीएनपी बहुमत से सरकार में आई है और

तारिक रहमान जो जिया उर रहमान के बेटे हैं, जिनकी माँ भी प्रधानमंत्री रही हैं, अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी सरकार के एक मंत्री जो हिंदू समुदाय से हैं, ( श्री चौधरी) ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि अल्पसंख्यकों को वेसे ही अधिकार होंगे जैसे बहुसंख्यकों को है। इस बयान के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में उठ रही शंकाओं का कुछ हद तक हल हुआ, और कुछ वातावरण भी बदला है। श्री तारिक रहमान भी लगभग 18 वर्ष के निर्वासन के बाद विदेश से लौटे हैं। वह सुशिक्षित व्यक्ति हैं, अगर वे राजनीति को प्रतिहिंसा का माध्यम नहीं बनायेंगे तो यह उनकी बड़ी सफ्फता होगी। हालांकि अभी हिंसा, प्रतिहिंसा के बादल मौजूद हैं। बंगलादेश के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया और यह एक प्रकार से एक दलीय चुनाव हुआ है। शेख हसीना की पार्टी वहाँ के चुनाव को रद्द करने की मांग कर रही है और यह आंदोलन बढ़ता, तो यह भी भारत के लिये एक समस्या बनेगा। बंगलादेश में श्रीमती हसीना के खिलाफ कई आघातिका मामले दर्ज हुए हैं जिनमें उन्हें आजीवन कारावास और मौलुयुंउद तक दिया जा सकता है। अभी तक बंगलादेश में हिंसा प्रतिहिंसा का चलन रहा है। बंगलादेश के जनक स्वरू शेख मुजीब की हत्या हुई उसके बाद जियाउर रहमान की हत्या हुई, उनकी पत्नी व रहमान को बाहर रहना पड़ा। मोहम्मद युनुस को बंगलादेश से निर्वासित किया गया। याने एक प्रकार से सत्ता के द्वारा प्रतिपक्ष व विरोधियों के दमन का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अभी थमा नहीं है। फिर तारिक रहमान उसे कैसे हल करेंगे, पुराने प्रतिहिंसा के रास्ते पर चलेंगे या उसे समाप्त करने के उपाय खोजेंगे यह कहना अभी संभव नहीं है। अपनी पीड़ाओं को भुलाकर अपने विरोधियों को भाफ करना, सम्मान देना, यह लोकतांत्रिक तो है परंतु मानसिक रूप से आसान नहीं है। फिर शेख हसीना के हटने के बाद बंगलादेश व पाकिस्तान के बीच पुराना याराना शुरू हुआ है। यद्यपि पूर्व स्थिति को बहाली तो संभव नहीं है परंतु मिलतीजुली विदेश नीति भारत के लिये चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है। शेख हसीना को बंगलादेश प्रत्यर्पित करने की मांग भी भारत व बंगलादेश के बीच एक टकराव का कारण बन सकती है। हालांकि अमेरिका के एक सीमित लक्ष्य की पूर्ति याने समर्थक और दोस्ती करने वाली सरकार हट गई है। पर अब यथार्थथिति को बनाये रखने का उद्देश्य हो सकता है।

नेपाल में भी जेन जी के नौजवानों ने अचानक आंदोलन शुरू किया था जिसमें भारी हिंसा हुई और अंत में सैन्य हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री का स्तौषण हुआ तथा श्रीमति काको को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया। वहाँ चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तीनों भृष्टे श्री चीन, प्रचंड तथा नेपाली कांग्रेस पूरी तरह पराजित हुए हैं और राष्ट्रीय

स्वतंत्र पार्टी के नाम से श्री वीरेंद्र शाह को जन समर्थन मिला है। श्री वीरेंद्र शाह को उनके दल ने बहुमत से प्रधानमंत्री पद के लिये उनका चुनाव किया। इससे अब नेपाल में फिर से सामंतवाद का जन्म हो सकता है। श्री वीरेंद्र शाह युवा हैं, परंतु उनका स्वभाव किना उग्र व अमर्यादित है जिसे एक घटना से जाना जा सकता है। चुनाव से पहले उनकी पत्नी की कार को पुलिस ने रोक लिया और श्री बालेन शाह वहीं पहुंचे तथा उन्होंने वहाँ कलम कि मैं तुम्हारी गद्दी को भी जला दूंगा। उनका यह बयान उनकी मानसिकता का परिचायक है। उनमें राजतंत्रीय घमंड है और ऐसा लगता है कि वह कानून कायदे को नहीं मानते।

यद्यपि श्री बालेन शाह ने कुछ शुरुआती निर्णय अच्छे किये हैं जैसे उन्होंने निजी शिक्षा बंदकर सारी शिक्षा को सरकारी करने की घोषणा की है। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के संपत्ति की जांच शुरू की है हालांकि उनका छात्र संघों के चुनावों पर रोक लगाने का निर्णय उचित मानते हैं। छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की पाठशाला होते हैं। और वे स्वतः ही छात्रों के आंदोलन के बाद ही चुनकर आये हैं। अमेरिका के लिये चीन समर्थक नेपाल मुह्रंद नहीं था और उससे मुक्ति पाने के लिये नेपाल में सत्ता परिवर्तन उसके अनुकूल है। फिर इन नये शासकों के चाहे बंगलादेश के तारिक रहमान हो, मोहम्मद युनुस हो, नेपाल के वीरेंद्र शाह हो, इन सभी के के आर्थिक तार अमेरिका के अनुकूल ही रहेंगे। उनकी भूमिका एक प्रकार से अमेरिका के लिये उनके हितों के संरक्षक,पोषक इरान के पूर्व शाह जैसी हो सकती है।

जेन जी या छात्रों के विद्रोह के नाम से जहाँ-जहाँ भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं, उनके कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं और एक प्रकार से वे वैश्विक शक्तियों के हितों के टकराव के माध्यम व कारण सिद्ध हुए हैं। अब बंगलादेश व नेपाल में क्या वही दोहराव होगा या कोई नई राजनीति या वैचारिक भूमिका का उदय होगा यह कहना संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात अवश्य है कि श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश के बदलाव के पीछे चाहे जो कारण रहे हो, इसमें दुनिया की शक्तियों की भूमिका रही हो, यह तो निश्चित है कि इन देशों के शासकों ने अपने देश का भविष्य बदलने की कोई चेष्टा नहीं की। वे भी पूर्व सत्ताधारी के समान यथरू स्थितियाँकरी, सत्ता लोत्तुप, भ्रष्ट, अपार संपत्ति को जोड़ते वाले सिद्ध हुए और वह आन जनता का विश्वास खो चुके थे। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि दुनिया की कोई भी सत्ता लंबे समय तक न तो जनता को गुमराह कर सकती, न दबा सकती और न ही उनकी आवाज को दबा सकती है। अब तो सरकारों को अपने आपको बदलकर जनमुखी बनना होगा या जाना होगा।

## बदलता भारत, नई रणनीति, नई शक्ति

**ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल**

**अंशुमान**

**लेखक संसद टीवी से संबद्ध पत्रकार हैं।**

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला केवल एक सुरक्षा घटना नहीं था, बल्कि उसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य रणनीति को नई दिशा देने का काम किया। इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकीवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आया। इसके बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसने वैश्विक स्तर पर साफ संकेत दिया कि अब भारत की नीति पहले जैसी सीमित और केवल प्रतिक्रिया देने वाली नहीं रही। सही मायनों में ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने केवल पाकिस्तान को सैन्य संदेश नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की बदलती रणनीतिक सोच दिखाई। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले हमलों को अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी से नहीं समांल जाएगा। अगर भारत की सुरक्षा पर हमला होगा, तो उसका जवाब तेज, सटीक और निर्णायक होगा। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि भारत अब स्ट्रेटिजिक रिस्पेंड यानी अत्यधिक संयम की पुनर्नीति से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है। पिछले 20 सालों में भारत को आतंकवाद के खिलाफ नीति कार्भी बदल गई है। 2001 में संसद पर हमला और 2008 में मुंबई हमला होने के बाद भारत ने ज्यादातर कूटनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय समर्थन का रास्ता अपनाया। उस समय भारत सीधे सैन्य कार्रवाई से बचना था। लेकिन 2016 के उरी हमले के बाद पहली बार भारत ने खुलकर सज्जित स्ट्राइक की। इससे यह साफ संदेश गया कि अब भारत सिर्फ बयान नहीं देगा, बल्कि आतंकीयों के ठिकानों पर जवाबी हमला भी करेगा। फिर 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक की, जिसमें सीमा पार जाकर कार्रवाई की गई। यह हमले से बड़ और ज्यादा आक्रामक कदम था। 2025 के पहलगाम हमले के बाद शुक्रवाह आऑपरेशन सिंदूर सिंदूर भी आगे

माना जा रहा है। इसे सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य ताकत और राजनीतिक इच्छाशक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक, ड्रोन, मिसाइल और तीनों सेनाओं के तालमेल का इस्तेमाल किया गया। रणनीतिक तौर पर देखें तो अब भारत का संदेश पहले से ज्यादा साफ माना जा रहा है अगर बड़ा आतंकी हमला होगा, तो उसका जवाब सीधे और सख्ती से दिया जाएगा इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने अपनी संरचना और युद्ध नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव शुरू किए। सबसे चर्चित बदलाव रहा रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो यूनिट्स का गठन। रुद्र ब्रिगेड को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान वाले इलाकों में तेज और घातक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। इन यूनिट्स का आकार पारंपरिक बड़ी सेना की तुलना में छोटा है, लेकिन इनमें ज्यादा मोबाइल, आधुनिक और आक्रामक बनाया गया है। इनका उद्देश्य है कि युद्ध या संकट की स्थिति में भारत बहुत कम समय में कार्रवाई कर सके और दुश्मन को संभलाने का मौका न मिले।

दूसरी ओर, भैरव यूनिट्स का गठन चीन और पाकिस्तान दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत को अब यह एहसास हो चुका है कि भविष्य के युद्ध केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे। चीन के साथ गलवान संघर्ष के बाद भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएँ बदल चुकी हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने पिछले कुछ वर्षों में सीमाओं पर भारी सैन्य ढाँचा तैयार किया है। इसके जवाब में भारत अब पहाड़ी युद्ध, हाई-टेक निगरानी और विशेष कमांडो यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नई रक्षा नीति का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब भारत दो मोर्चों वाले खतरे यानी चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। पहले भारत की अधिकांश सैन्य तैयारी पाकिस्तान केंद्रित होती थी, लेकिन अब चीन को बड़ा और दीर्घकालिक खतरा माना जा रहा है। यही कारण है कि भारत अपनी सेना को अधिक तकनीकी, तेज और संयुक्त युद्ध क्षमता वाली सेना में बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत की नई रणनीति में तकनीकी भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। सेना में शौर्य स्टाइलन मार के ड्रोन यूनिट्स जोड़े जा रहे हैं। ये ड्रोन निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, सटीक हमला करने और

इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में मदद करेंगे। रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और मिसाइलें पारंपरिक टैंकों और भारी सेना से कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं। भारत अब इसी दिशा में तेजी से निवेश कर रहा है।

2025 में हुए त्रिशुल सैन्य अभ्यास ने भी भारत की नई सोच को सामने रखा। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि भविष्य में भारत तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़कर 'मल्टी-डोमेन वॉरफेयर' यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करना चाहता है। आधुनिक युद्ध अब केवल सीमा पर सैनिक भेजने तक सीमित नहीं है। अब साइबर हमला, स्पेस टेकनॉलोजी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन, मिसाइल और सूचना युद्ध भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं।

ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा भू-राजनीतिक संदेश भी था। भारत ने केवल पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी, बल्कि चीन, अमेरिका, रूस और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों की भी यह संकेत दिया कि अब भारत अब एक 'एंपाइटव पॉवर' नहीं बल्कि 'प्रोएक्टिव सिक्वोरिटी पॉवर' बनना चाहता है। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में सक्षम शक्ति है।

यह संदेश खासतौर पर चीन के लिए महत्वपूर्ण था। चीन पिछले कुछ वर्षों से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बन्टोटा पोर्ट और हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियाँ भारत के लिए चिंता का विषय हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का सैन्य आधुनिकीकरण केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है।

भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी यह संदेश दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ जोरो टॉलेंस नीति अपनाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर चुका है। क्वाद जैस मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ी है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि भारत केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक उभरती हुई सैन्य शक्ति भी बनना चाहता है।

हालांकि इन सब बदलावों के बावजूद भारत की रक्षा

व्यवस्था में कई बड़ी चुनौतियाँ अभी बाकी हैं। सबसे बड़ी समस्या है इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड का न बन पाना। अमेरिका और चीन जैसे देशों में सेना, वायु सेना और नौसेना एक संयुक्त कमांड के तहत काम करती हैं। लेकिन भारत में अभी भी तीनों सेनाओं के बीच पूरा तालमेल नहीं बन पाया है। युद्ध के समय तेज निर्णय और संयुक्त कार्यवाही के लिए थिएटर कमांड बहुत जरूरी मानी जाती है। इसी तरह भारत अभी तक इंटिग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी आईआरएफ भी नहीं बना पाया है। चीन के पास पहले से शक्तिशाली रॉकेट फोर्स है और पाकिस्तान ने भी अपना रॉकेट कमांड तैयार कर लिया है। भविष्य के युद्धों में लंबी दूरी की मिसाइलें, प्रिसिजन स्ट्राइक और रॉकेट सिस्टम निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसलिए भारत के लिए भी ऐसी संयुक्त रॉकेट फोर्स बनाना समय की जरूरत बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा नीति में एक और बड़ा बदलाव यह देखने को मिला कि देश की रणनीति फिर से महाद्वीपीय सुरक्षा यानी जमीन आधारित खतरों की ओर ज्यादा झुक गई है। इसका असर नौसेना की कुछ बड़ी योजनाओं पर भी पड़ सकता है। जबकि चीन की बढ़ती समुद्री ताकत को देखते हुए भारत के लिए हिंद महासागर में मजबूत नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आने वाले वर्षों में भारत को जमीन और समुद्री सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। यह भारत की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति और बदलते भू-राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वह एशिया की शक्ति राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है।

कुल मिलाकर, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति में एक नए दौर की शुरुआत की है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तेजी से बदलना चाहता है। लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब भारत केवल नए हथियार खरीदने तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी सैन्य संरचना, निर्णय प्रणाली, तकनीकी क्षमता और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को भी पूरी तरह आधुनिक बनाए। आने वाले दशक में यही तय करेगा कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति बनता है या वास्तव में एक वैश्विक सामरिक शक्ति के रूप में उभरता है।

## कोई तो दे जवाब, देश क्या है, कौन है?

**अभिव्यक्ति**

**धरुव शुक्ल**

लेखक साहित्यकार हैं।

**तया** देश सिर्फ दुकान है कि जब चाहे खोल दी, जब चाहे बंद कर दी? क्या देश किसी की जायजाद है कि जब चाहे खरीद ली, जब चाहे बेच दी, जब मन आये सो किराये पर उठा दे? देश नौकरी भी नहीं है कि करके छोड़ दो, छोड़ी पा ली। देश दिल नहीं है कि लूट गया। दिल्लो भी नहीं है कि लूट ली। दिल्ली भी नहीं है कि जब चाहे सो कर ली। देश कबसे अपना है ? क्या देश कोई सपना है? क्या देश केवल तपन है, खपान है? क्या देश कोई काबा है, कलौसा है, चर्च है या केवल जीवन का मनमाना खर्च है? क्या देश गाली-गलौज है, भ्रष्ट नेताओं की मौज है?

क्या देश कोई मूख है, पादरी है, संत है? आखिर देश किसकी सत्तामती है और किसका अंत है? देश पर किसका दावा है, वह किसकी दलील है? देश किसके हुूम की तामील है? देश किसका वकील है? क्या देश सिर्फ मोंद है? क्या देश सिर्फ मस्जिद है? आखिर देश किसकी जिद है? देश किसका जरिया है, किसकी मुाद है? देश कबसे आबाद है और क्यों बखाद है? क्या देश बसेबसे लोगों का मैन है? आखिर देश क्या है और कौन है?

आखिर देश क्या है? क्या नदी को हिलोार है, लोगों का शोर है या कोई सीनाजोर है? क्या सागर की पछाड़ है, बाघ की दहाड़ है या कोई ऊंचा पहाड़ है? स्वर है, ताल है, लय है या कोई भय है? क्या देश कोई राग है या सिर्फ भागमभाग है? क्या वह हडकम्म है, हड़ताल है? भूकम्प है, तुफान है, बाढ़ है, अकाल है? क्या देश सिर्फ महगी दाल है? क्या देश की मला है, ममता है, मन का मलाल है? देश किसका धर्म है, देश किसका मर्म है, देश किसका कर्म है, देश किसकी शर्म है? क्या देश जनता का

बल है या केवल राजनीतिक छल है? क्या देश जीवन की आस है या राजनीतिक दलों की बकवास है?

क्या देश कोई जेन-ऊन्दन है या केवल स्वार्थ का राजनीतिक गठबंधन है? क्या देश आपस की फुट है और केवल जन्मत की लूट है? क्या देश कोई बंदर है, भालू है, मदारी है, जो गाँठ ले उसकी सवारी है? क्या देश कोई पालतू हाथी है, घोड़ा है, कोई अंकुश और कौड़ा है या धरती की छती पर पका हुआ फोड़ा है? क्या देश कोई खिला हुआ फूल है या सीने में रोज चुभता कोई शूल है? देश आखिर किसके हिस्रे का काट है? देश किसका मन है जो खोटा है? क्या देश केवल राजबिहार है? क्या देश कोई लड़खूझती सरकार है? क्या देश केवल राजनीतिक यथार्थ है या कोई परमार्थ है?

क्या देश सिर्फ सुख है या अनंत व्याधि है? समय है, सदी है, काल है या कोई भ्रमजाल है? क्या देश सिर्फ कुदरत का कमाल है? आचार है, विचार है या सिर्फ चुनाव विचार है? क्या देश कोई बक-बक है, झुगाइटकी है? देश में किसकी साँस कहीं अटकती है? देश किसका पुण्य है, किसका पाप है या केवल प्रलाप है? क्या वह सबका सितारहार है? क्या वह सबका पालनहार है या केवल संहार है? देश किसके बागों की बहार है, वह किससे इरुमनी है और किससे प्याह है?

क्या देश सिर्फ हिन्दू है? क्या वह सिर्फ मुसलमान है या सिर्फ क्रिश्चन की तात है? देश किसका मकान है, किसकी दूकान है, क्या वह केवल लूट का सामान है? क्या देश जीवन की जीत है या जीवन की हार है? आखिर देश किसकी पुकार है? क्या वह देव है, दानव है या सिर्फ मानव है? पशु है, पक्षी है, फूल है या सिर्फ कूड़ा-ककट है, कोई मरूट है? क्या देश जीवन का मेला है? क्या कोई किसी के साथ नहीं, हर कोई अकेला है? क्या देश बलता पानी है या किनारों पर दही कोई पुनोि कढ़नी है? कौन है पुत और कौन है कपूत? आखिर क्या है देश-भक्त का सन्त?

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

**प्रधान संपादक**  
उमेश त्रिवेदी  
**कार्यकारी प्रधान संपादक**  
अजय बोक्लि  
**संपादक (मध्यप्रदेश)**  
विनोद तिवारी  
**वरिष्ठ संपादक**  
पंकज शुक्ला  
**प्रबंध संपादक**  
अरुण पटेल  
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)  
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,  
Ph. No. 0755-2422692, 4059111  
Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का रहस्यत होना आवश्यक नहीं है।

**ख़बर**

**आसिम अनमोल**

लेखक व्यंग्यकार हैं।

पिछले दिनों सरकार कुत्तों के लिए सख्त हो गई। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों को आदेश दे डाले गए। आवारा कुत्ते पकड़ के लाओ। एक नहीं छूटना चाहिए। कर्मचारियों के होश उड़ गए। उनके दिमाग का पारा गरम हो गया। इन कुत्तों की पी टी उपा माफ़िक स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। यह सुनकर कुत्तों को पकड़ने का जारी किया गया आदेश घबरा गया। आवारा कुत्तों की लाइफ भी देश की राजनीति से कम नहीं होती। जैसे राजनीति चारों दिशाओं में अपने सम्बोधन के सहारे देश की चारों दिशाओं में भागभाग करती रहती है वैसे ही कुत्तों का मानव जाति पर गली कुत्तों में किए जा रहे जानलेवा हमले भी जोरदार भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी पाबंदियां इन पर रूआब दिखाकर इनको कैसे पकड़ में ला पाँगी। यह सवाल भी पूरे देश में कुत्तों की तरह मारा मारा फिर रहा है। इधर कर्मचारियों की भी जान आफत में है। रोजाना नगर निकाय में रिपोट पेश करने का प्रेशर अलगा। कर्मचारियों को खुद के परिवार के बारे



में कम कुत्तों के बारे में ज्यादा चिंतन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की इतनी मनः स्थिति खराब है कि रात को नींद में कुत्तों के स्वरप से पतियाँ परेशान हैं। सुबह की गुड़ मॉनिंग दरवाजे से गुजर रहे मोहल्ले के कुत्तों से हो

रही है। मेरे मोहल्ले में एक रोज नगर निकाय की गाड़ी मय कर्मचारियों के पथारी। गाड़ी आगे आगे कुत्ते पूछ हिलाते हुए पीछे पीछे धाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी क कुत्तों को पकड़ने नहीं बल्कि कुत्ते नगर निकाय की गाड़ी

को पकड़ने के लिए रिपार से भाग रहे हों। हमारे देश में पकड़ने की पकड़ हर स्तर पर बहुत कमजोर है। किसी चोर का गिरवां धोके से पकड़कर दिखा दो। छुड़वाने वाले मय पनसेले लेकर सैकड़ों जमा हो जाएँगे समाज सेवक बनकर। पकड़ तो काले धन की भी नहीं हो पाई थी। वो भी पूरे देश में कुत्तों की तरह मारा मारा फिरा था। कर्मचारी कुत्तों को लेकर बहुत परेशान हैं। कुत्ते बिलकुल नहीं परेशान हैं। वो उच्छ्र्त कूद करके खुश हो रहे हैं। तुम अपना जाल तैयार रखो। हम उच्छ्र्त उच्छ्रलकर गली कुत्तों में भागने का प्रयास कर लेंगे। हम तुमको दिखेंगे ही नहीं। हम चुपके से घरों में चुस जाएँगे। पलंग के नीचे जाकर सो जाएँगे। जब तुमको हम दिखेंगे ही नहीं तो तुम हमको कैसे पकड़ पाओगे। जब तुम थक होर मानकर अपने नगर निगम के मय आदेश के उदास हारकर चले जाओगे। फिर हम सीना तानकर सड़कों पर बादशाहत करने आ जाएँगे। इसानों के सपने तो जीवन में कभी न कभी पूरे हो ही जाते हैं। इधर कुत्तों को पकड़ने का सपना सरकार का आदेश बनकर सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। उधर कुत्तों के द्वारा इस सपने को ध्वस्त करने की योजना कर्मचारियों के हैसलतों पर चार कर रही है।

# मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार

**मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये। अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं।**

राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करते हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या बहुमत खो देता है और फिर भी इस्तीफा देने से इंकार करता है, तो राज्यपाल को उन्हें पद से हटाने का अधिकार है। संवैधानिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करते हुए, मौजूदा सरकार को हटाने के लिए औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है।

स्थापित परंपराओं के अनुसार, राज्यपाल सरकार के बहुमत की जांच के लिए विधानसभा का विषय सत्र भी बुला सकते हैं। वर्तमान संख्या को देखते हुए, ममता बनर्जी के लिए बहुमत साबित करना असंभव होगा। ऐसे में सदन में उपस्थित न होने पर मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यपाल सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यूनतम मतदान के माध्यम से बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकता है। इसका पालन न करने पर संवैधानिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम मतदान से बचने को बार-बार सचेत किया है।

यदि संवैधानिक गतिरोध बना रहता है, तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है। ऐसे मामलों में, राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। एक बार लागू होने पर, शासन केंद्र के हाथों में चला जाता है, जिससे मुख्यमंत्री का अधिकार प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या कोई स्थिर सरकार गठित न हो

सके। हालांकि, बोम्बई फैसले के बाद, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर काफी हद तक रोक लगी। आज, राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक रूप से अंतिम उपाय माना जाता है, न कि राजनीतिक शॉर्टकट। राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले आमतौर पर सरकार गठन, गठबंधन निर्माण या

विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियाँ राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।

मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे छह महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर छह महीने तक सदन की सदस्यता हासिल नहीं की जाती है तो मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रहेगा। संविधान का

अनुच्छेद 164 (1) कहता है कि मुख्यमंत्री 'राज्यपाल की इच्छा तक' पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल की इच्छा दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों (विधायकों) के बहुमत द्वारा किसी एक नेता पर जताए गए भरोसे से तय होती है।

हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते, तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों (विधानसभा और विधान परिषद) के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक, उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष का होता है। पांच साल का वक्त पूरा होते ही यह खुद ब खुद भंग हो जाएगी। अनुच्छेद 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी। पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। संविधान के अनुसार, पद पर बने रहने के मामले में मुख्यमंत्री राज्यपाल के डेप्युटी ऑफ प्लेजर (राज्यपाल की इच्छा का सिद्धांत) के तहत कार्य करते हैं।

पहले भी ऐसी स्थितियाँ रही हैं जब मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत खो दिया था। ऐसे मामलों में राज्यपाल ने किसी अन्य नेता को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए ऐसी स्थिति में राज्यपाल निश्चित रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ी निर्वाचित पार्टी के नेता को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के पास नई सरकार के गठन का विरोध करने का कोई वैधानिक अधिकार है। ममता बनर्जी का बयान एक राजनीतिक बयान ज्यादा है। इसका उद्देश्य सहानुभूति हासिल करना है। यह कोई संवैधानिक कदम भी नहीं है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में, जब मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत होता है, तब राज्यपाल इस डेप्युटी ऑफ प्लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्तमान परिवेश में ममता की पार्टी का सदन में बहुमत नहीं है। इसलिए ममता दीदी के बयान को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत बहुमत वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के पद की शपथ हेतु आमंत्रित कर सकते हैं।



**कानून और न्याय**  
**पश्चिम बंगाल चुनाव**  
**विनय झैलावत**  
(पूर्व अक्सिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपने पद से इस्तीफा न देने का उनका बयान चर्चाओं में रही। उनके इस बयान पर बीजेपी से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी राय जाहिर की है। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद मंगलवार को ममता बनर्जी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में चुनाव को जबरन अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। अब राज्यपाल द्वारा ममता सरकार और मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया है तथा सुवेन्दु अधिकारी को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। ममता को कुछ भी कहे, लेकिन इस संबंध में हमें कानूनी प्रक्रिया को समझना होगा। यह भी देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है? चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव को चुनौती कैसे दी जाएगी? विचारणीय प्रश्न यह है कि किसी मुख्यमंत्री का यह कहना कि वह इस्तीफा नहीं देंगी, क्या कानूनी रूप से सही है? यह भी विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसी स्थिति में भी वे मुख्यमंत्री रहेंगी? हमारे लिए इस संबंध में यह जानना आवश्यक है कि इस संबंध में भारतीय संविधान आखिर क्या कहता है?

इस संबंध में भारत के संविधान का भाग 6 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 236 तक शामिल है। इन अनुच्छेदों में राज्य के शासन की प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इन्हें में से कुछ अनुच्छेद मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्रियों से जुड़े हैं। अनुच्छेद 163 और 164 के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान, मुख्यमंत्री रहेगा। हारे हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। संवैधानिक ढांचा बहुमत खो देने पर प्रभावी रूप से यही अनिवार्य करता है। संवैधानिक परंपराएं केवल राजनीतिक शिष्टाचार नहीं हैं। न्यायालय लोकतांत्रिक शासन की व्याख्या करते समय अक्सर इन्हें मान्यता देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि विधायिका में बहुमत संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है। कार्यपालिका की वैधता पूरी तरह से निर्वाचित सदन के विश्वास पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से दृढ़ता से स्थापित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, मुख्यमंत्री



**श्रीति राशिनकर**

गर्मी के दिन आते ही याद आती है घर के छत की ! छत या जिसे गच्ची कहा जाता था ,बचपन की ऐसी जगह जो हर बच्चे को अपनी सी लगती थी । आज जगह की कमी और शहरी संस्कृति ने गच्ची को बालकनी तक सिमटा दिया है । यह वो समय था जब गच्ची पर हम बेखौफ सोते थे , न किसी का डर होता था न किसी का खौफ । आज जब पुराने दिनों कि यादें ताजा करने की कोशिश करती हूँ तो जागजीतसिंह और चित्रासिंह की गुजूल - हम तो है परदेस में , देश में निकला होगा चाँद याद जल्द आती है । बचपन में माँ की लोरी का चाँद हो या फिर दादी की कहानी का गोलमटोल सा हैसता चाँद व्यक्ति को जीवन भर याद रहता है । यह सच है कि बचपन में देखा हुआ चाँद युवा और बुजुर्ग अवस्था के चाँद से बिलकुल अलग होता है क्योंकि वह हमारे कल्पना का चाँद होता है। वास्तविकता से बिलकुल अलग । यह नन्हा सा चाँद एक बड़ा आकर्षण होता था छत पर सोते समय । उन दिनों बड़ी लम्बी होती थी गर्मी की छुट्टियाँ , परीक्षा खत्म होने से पहले ही पूरी योजना



**मातृ दिवस**  
**सीमा देवेन्द्र**  
लेखक साहित्यकार हैं।

समाज क्या चाहता है माँ से ? देश को क्या उम्मीद है माँ से ? और माँ भी कहीं ना कहीं यही चाहती होगी कि मेरे लालन पालन में कोई कसर बाक़ी ना रहे , कोई मुझ पर उँगली ना उठाए । ये चिंतन और विमर्श के विषय हैं लेकिन आधुनिकता सब पर भारी पड़ रही है । गिफ्ट लेन देन फोटो पार्टी ये सब आधुनिक चॉसलिए इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि मूल मुद्दे से सब दूर हैं । यदि देश को फिर से विवेकानंद आजाद भगतसिंह और शिवाजी चाहिए तो वह माँ ही है जो पुनः लौटा सकती है , अपने लाल को इस तरह तैयार कर सकती है । इसके लिए माँ का जागरूक होकर अपने व्यक्तित्व में सख्ती लाकर अपनी छाप छोड़ना बहुत जरूरी है । वनाँ माँ ममता की मूरत तो है ही । सुबह से शाम तक घर का काम करती है सबका ध्यान रखती । और फिर ये काम माँ ही तो करती है ये भी निश्चित है । मैं इससे किसी माँ का मूल्यांकन कम नहीं आँक रही , बल्कि इसे और ऊँचा दर्जा देने की बात कर रही हूँ जहाँ माँओं ने इतिहास रचे हैं ।

## वो छत, गर्मी की रातें और यादों में बसी बातें

**दिन भर मस्ती , खाना-पीना , धमाचौकड़ी में समय कहां बित जाता मालूम ही नहीं पड़ता और शाम हो जाती जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता । हर रोज गच्ची कि झाड़ू बारी बारी से लगाई जाती । इस पर भी झगड़े होते , बड़े बच्चे कहते रोज रोज हम ही क्यों लगाये झाड़ू ,छोटे बच्चे भी तो सोते है ना ? फिर माँ आकर सबको बराबरी से काम बाँटती । इसके बाद बाल्टियों में पानी लाकर छत पर पानी छिड़का जाता , दिनभर की तपन रफूचक़र हो जाती और गच्ची शीतल जल से तरताजा हो जाती ।ठंडी बयार चलने लगती और छत पर फैली रातरानी की बेल संपूर्ण वातावरण को सुरभित कर देती। गच्ची पर खाना खाने का आनंद ही अलग होता था । हर बच्चा कोई थाली तो कोई कटोरी गिलास ऊपर लेकर आता ।**

बना ली जाती थी । मामा ,काका बुआ के बच्चें भी पास के गाँव से रहने आते थे और फिर शुरू होता था हमारा अपना ग्रीष्मकालीन शिविर !

दिन भर मस्ती , खाना-पीना , धमाचौकड़ी में समय कहां बित जाता मालूम ही नहीं पड़ता और शाम हो जाती जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता । हर रोज गच्ची कि झाड़ू बारी बारी से लगाई जाती । इस पर भी झगड़े होते , बड़े बच्चे कहते रोज रोज हम ही क्यों लगाये झाड़ू ,छोटे बच्चे भी तो सोते है ना ? फिर माँ आकर सबको बराबरी से काम बाँटती । इसके बाद बाल्टियों में पानी लाकर छत पर पानी छिड़का जाता , दिनभर की तपन रफूचक़र हो जाती और गच्ची शीतल जल से तरताजा हो जाती ।ठंडी बयार चलने लगती और छत पर



फैली रातरानी की बेल संपूर्ण वातावरण को सुरभित कर देती। गच्ची पर खाना खाने का आनंद ही अलग होता था । हर बच्चा कोई

खाना गिरा दोगे तो अन्न का नुकसान होगा , उस उम्र में माँ ने खेल खेल में अन्न का महत्व समझा दिया था जो आज भी जेहन में है । हंसी-ठिठोली के साथ कभी आम के रस के साथ न जाने कितनी पुडियाँ हम खा जाते , तो कभी लौंजी ,पुदीने की खट्टी मीठी चटनी का स्वाद भोजन को स्वादिष्ट बनाता ।

खाने के बाद सभी बच्चे लम्बी दूरी बिछाने उस पर गहियँ और सफेद झक चादरें बिछाई जाती। माँ और पिताजी चादरे बिछाने पर देखते की किसकी चादरों में कितनी सलवटे हैं , फिर सलवटे हटाकर उसे टीक करना सिखाया जाता । गहियँ पर बच्चे कतारबद्ध लेट जाते । आसमान की ओर नजर जाते ही असंख्य तारों को हम अपनी आँखों में समाने कि कोशिश करते ।

फिर शुरू होता चांदनी को गिनने का खेल ! जहाँ से शुरू करते वहाँ आकर रुकने में ही सब उलझ जाते और गिनना अधूरा रह जाता , शायद तभी से तारे गिनने कि कहवात ऐसी ही शुरू हुई होगी। इसी बीच सप्तर्षि ,आकाश गंगा देखते देखते हम नींद के आगोश में समा जाते पर हाँ उनींदी आँखों से माँ को कहते रात को चार बजे हमें ध्रुव तारा देखने के लिए उठा देना । दूसरे दिन माँ बताती की कई कोशिशों के बावजूद हम गहरी नींद में सोते ही रहते। दूसरे दिन सब मिलकर खूब हँसते । आज बरसों बित गए हैं , चन्द्रमा और तारों तो सदियों से चले आ रहे हैं ,लेकिन बिना कूलर ,पंखे और एसी की गच्ची पर गहरी नींद का आनंद आज भी हमें खुशनुमा एहसास से भर देता है।

## माँ ही लौटा सकती है पुनः आजाद और भगतसिंह

**माँ तिरी सख्तियाँ तिरे ऊसूल सलामत रहे, तिरी परवरिश पर किसी को न शिकायत रहे ।।**

देखा जाय तो हर हालात माँ से होकर ही गुजरते हैं क्योंकि माँ ही परिवार की धुरी होती है । बालक के व्यक्तित्व निर्माण के मूल में माँ होती है । कहा भी गया है कि माँ ही बालक की प्रथम गुरु होती है । मातृत्व केवल जन्म देने की प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की दीर्घकालिक साधना है । बाल्यावस्था से ही बालक के सोच और व्यवहार को दिशा मिलना प्रारम्भ हो जाती है जो धीरे धीरे संस्कार बनते जाते हैं । यही शिक्षा बिना किसी पाठ्यक्रम के जीवन जीने की कला सिखाती है । आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य में माँ की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है । जो बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा , नैतिक शिक्षा और मनसिक संतुलन का आधार है ।

दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं क्योंकि समाज के लिए ये एक आत्ममंथन का अवसर बनें । माँ का प्रभाव ही वह बीज है जिससे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व और सुदृढ़ समाज विकसित होता है । इसलिए मातृत्व को सामाजिक और नीतिगत स्तर पर सशक्त होना बहुत जरूरी है । माँ का प्रभाव ही



बालक के जीवन को आकार देता है । यदि हम हमारी पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी वाली माँ की बात करें तब वह मैं बहुत ही सीधी सरल और ज्यादातर निरक्षर होती थी लेकिन उनका प्रभाव - संस्कार

साथ प्रेम की प्रतिमूर्ति होना , और जिसमें ये सब गुण होते हैं वही तो माँ होती है । लेकिन बालक जब इन गुणों का दुरुपयोग करने में समझने लगे तब सख्त होने की आवश्यकता होती है जो अतिआवश्यक है । ये सख्तियाँ आयी भी हमारी पीढ़ी वाली माँओं में । हाँलाकि इतिहास पलटकर देखें तो ऐसी माँओं का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है जहाँ माँ ने अपने मातृत्व वाले गुणों को हृदय में दबाकर उनको देश और सच्चाई के पथ पर न्यौछार किए हैं । बात करें तो हर युग में ये भी देखा गया है , कई बार बाहरी माहौल बाहरी ताकतें इतनी सशक्त होती है कि माँ के दिए संस्कार कमजोर पड़ने लगते हैं जो कि आज के हालात से स्पष्ट हो रहे हैं । महागरों में संस्कारित परिवार की युवतियाँ अपने मातृत्व को एक तरफ रख अपने माता पिता को शर्मसार कर रही है । इस आचरण से वे अपने बच्चों पर क्या प्रभाव छोड़ेंगी उन्हें खुद नहीं पता । जो हमारे सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है ।

जहाँ समाज की संरचना संयुक्त परिवार पर आधारित है वहाँ इस तरह की महिलाएँ अपने बच्चों को वो कीमती समय नहीं दे रही जो उन्हें देना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी अनैतिक दिनचर्या से ही फुसलती नही ( कड़वा है मगर सत्य है ) । ऐसी स्थिति में उन नौनिहालों का भविष्य चिंतनीय है जिसका भुगतान भी पीढ़ीयाँ करेंगी । आजकल जैसे ही स्क्रीन की चमक ने कई रिश्तों को धुँधला कर दिया है । लेकिन वही समय होता है वही अवसर होता है जहाँ मानवता अपनी छाप छोड़ती है । हर युग में माँ की सख्ती प्रथम है । माँ अपने अनुभवों से परिस्थितयों से संवेदना और संस्कार की नई परिभाषा गढ़ सकती है । वह उस पीढ़ी की सुजक है जो राष्ट्र के भविष्य को आकार देती है । माँ एक जिम्मेदारी है । जहाँ ममता लाड़ प्यार जरूरी है एक सीमा तक वहीं सख्तियाँ और अनुशासन वाली जागरूकता भी कहीं अधिक जरूरी है । यही प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास को निर्देशित कर उसे स्वाभाविक रूप से जीवन जीने की प्रेरणा बनता है । माँ का प्रभाव पीढ़ियों तक गूँजता है । जागरूक माँ एक बेहतर समाज और राष्ट्र की पहली शिल्पकार होती है ।



## संक्षिप्त समाचार

### पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेकर स्वयं की वर्कशॉप प्रारंभ की, मासिक आय 10 हजार हुई

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले की नटेरन तहसील के रहने वाले श्री भारत सिंह पुत्र छक्कलाल ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेकर अपनी मासिक आय 10 हजार रुपये कर ली है उन्होंने स्वयं की वर्कशॉप प्रारंभ कर इस उपलब्धि को हासिल किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित हितग्राही श्री भारत सिंह ने बताया कि उन्हें प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में अपने क्षेत्र के जनपद कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रशिक्षण आईटीआई विदिशा से बास्केटमैकर जॉब रोल में प्राप्त किया, योजना के तहत उन्हें एक लाख रुपये की लोन राशि प्राप्त की जिसमें उन्होंने वर्षा ग्राम में स्वयं की दुकान प्रारंभ की है। इस योजना ने उनका जीवन बदल दिया है एवं आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने में सहायता प्रदान की है।

### जनगणना-2027 मकान सूचीकरण में अच्छा कार्य करने वाले सुपरवाइजर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में जनगणना-2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण में रायसेन जिले के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में सर्वप्रथम, उत्कृष्ट और शत-प्रतिशत कार्य को पूर्ण करने वाले 40 सुपरवाइजर्स का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी ने सभी उपस्थित सुपरवाइजर्स को जनगणना में किए गए शत-प्रतिशत और उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की, साथ ही सुपरवाइजर्स द्वारा अपना-अपना कार्यों का अनुभव भी सांझा किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला पंचायत सीईओ श्री सोलंकी द्वारा सुपरवाइजर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

### एसडीएम ने देर रात उपार्जन केंद्र पहुंचकर मुख्य मार्ग पर खड़े कृषि वाहनों को करवाया व्यवस्थित

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में एसडीएम सिवनी मालवा विजय राय द्वारा बीती रात क्षेत्र के विभिन्न उपार्जन केंद्रों/वेयरहाउसों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार, केंद्रों के बाहर सड़क पर खड़े वाहनों की लंबी लाइनों को व्यवस्थित कर केंद्र परिसर के भीतर खड़ा करवाया गया। जिससे मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े होने के कारण कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। आपातकालीन स्थिति में यदि कोई वाहन सड़क किनारे खड़ा होता है, तो वह दूर से ही दिखाई दे सके, इसके लिए वाहनों पर रेडियम की पट्टियां लगाना अनिवार्य किया गया है। मौके पर उपस्थित एसडीएम ने स्वयं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रेडियम की पट्टियां चिपकाईं। साथ ही उन्होंने किसानों और चालकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। समिति प्रबंधकों और वेयरहाउस मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में वाहन सड़क पर अस्त-व्यस्त न खड़े हों। इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि रात के समय सड़कों के किनारे खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली अंधेरे के कारण पीछे से आने वाले वाहनों को दिखाई नहीं देते, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रेडियम की पट्टियां वाहनों पर चस्पा की गईं ताकि वाहन दूर से ही चमके, एवं आने जाने वाले वाहन सावधानी के साथ निकल सकें और दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा।

### सहायक आयुक्त ने विकासखंड शिक्षा कार्यालय शाहपुर का किया औचक निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। जनजातीय कार्य विभाग बैतूल के सहायक आयुक्त ने बुधवार को विकासखंड शिक्षा कार्यालय शाहपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में संघारित रोकड़बूझ, सेवा अभिलेख एवं कर्मचारी उपस्थिति पंजी का बारीकी से अवलोकन किया गया। निरीक्षण में कुछ सेवा अभिलेखों में अवकाश लेखा अपूर्ण पाए जाने के साथ ही सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ, जिसमें जन्मतिथि अंकित होती है, पर आवश्यक रूप से सेलो टेप नहीं लगाए जाने की आपत्ति दर्ज की गई। इस पर अधिकारियों को आवश्यक सुधार करते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराए जाने से बचने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा निलंबित कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी गंभीरता जताई गई। जिन कर्मचारियों का मुख्यालय निर्धारित किया गया है, उनके द्वारा प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनकी उपस्थिति नियमित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

### रेत, गिट्टी और बोल्टर के अवैध परिवहन में सिलित 3 वाहनों को किया जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को खनिज विभाग द्वारा खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अमले द्वारा गौण खनिजों के अवैध परिवहन में सिलित वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। खनिज प्रशासन उप संचालक एवं खनिज निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ मुलताई क्षेत्रांतर्गत ग्राम परमंडल के पास से खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन में सिलित 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 0625 को जप्त कर पुलिस थाना साईंखेड़ा की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। वहीं, बैतूल क्षेत्रांतर्गत बैतूल बाजार के पास से खनिज बोल्टर के अवैध परिवहन में सिलित 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमएच 12 डब्ल्यूजे 9371 को जप्त कर पुलिस थाना बैतूल बाजार की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। इसके अलावा चक्कर रोड कमाना गेट के पास से खनिज रेत के अवैध परिवहन में सिलित 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 28 एच 2414 को जप्त कर पुलिस थाना गंज बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। उपरोक्त अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रकरण को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

# वन स्टॉप सेंटर की संवेदनशील पहल से 85 वर्षीय महिला अपने परिवार से मिलीं

विदिशा (निप्र)। मानवीय संवेदनाओं, त्वरित सहायता और प्रशासनिक समन्वय का एक प्रेरणादायक उदाहरण विदिशा जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिला कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा के मार्गदर्शन एवं वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक श्रीमती कृतिता व्यास के अथक प्रयासों से एक 85 वर्षीय वृद्ध महिला को सुरक्षित रूप से उनके परिवार तक पहुंचाया गया। यह पहल न केवल प्रशासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली को दर्शाती है, बल्कि मानवता और सेवा भावना की उत्कृष्ट मिसाल भी बनी है। जानकारी के अनुसार वृद्ध महिला, जिनका परिवर्तित नाम इंदुबाई रखा गया, गलती से गलत ट्रेन में बैठ गई थीं, जिसके कारण वे अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर विदिशा पहुंच गईं।

अपरिचित स्थान पर पहुंचने के बाद महिला असहाय एवं भ्रमित अवस्था में भटक रही थीं। दिनांक 22 अप्रैल 2026 को मेडिकल कॉलेज परिसर में महिला अस्वस्थ हालत में मिलीं। इस संबंध में पत्रकार श्री कोमल प्रसाद द्वारा सूचना दिए जाने पर वन स्टॉप सेंटर की टीम तत्काल सक्रिय हुई। वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला का रेस्क्यू कर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उस समय महिला मानसिक एवं शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर थीं तथा अपनी पहचान अथवा निवास संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से देने की स्थिति में नहीं थीं। ऐसी परिस्थिति में वन स्टॉप सेंटर की टीम ने संवेदनशीलता एवं धैर्य के साथ



उनकी देखभाल प्रारंभ की। अस्पताल में उपचार के दौरान सेंटर स्टाफ एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा नियमित रूप से महिला की सेवा की गई। उन्हें समय पर भोजन, दवाइयां एवं आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराई गई। निरंतर देखभाल एवं उपचार के कारण धीरे-धीरे महिला के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। वन स्टॉप सेंटर

## प्रोजेक्ट सुरक्षा के तहत सोहागपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लगाई गई रेडियम पट्टियाँ



किसी रिफ्लेक्टर अथवा संकेत के चलने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली अन्य वाहनों के लिए खतरा बन जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने स्वयं मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों

के पीछे रेडियम स्ट्रिप लगावाईं, ताकि वे दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। उपार्जन केंद्र पर उपस्थित एवं कतार में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर भी रेडियम पट्टियाँ लगाई गईं, जिससे रात्रिकालीन आवागमन के दौरान उनकी दृश्यता बढ़ सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इस अवसर पर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक सावधानियाँ बरतने की अपील भी की गई। प्रशासन द्वारा कहा गया कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

के पीछे रेडियम स्ट्रिप लगावाईं, ताकि वे दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। उपार्जन केंद्र पर उपस्थित एवं कतार में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर भी रेडियम पट्टियाँ लगाई गईं, जिससे रात्रिकालीन आवागमन के दौरान उनकी दृश्यता बढ़ सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इस अवसर पर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक सावधानियाँ बरतने की अपील भी की गई। प्रशासन द्वारा कहा गया कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

## जिले में सड़क सुरक्षा को नई दिशा देने के लिए प्रारंभ हुआ नवाचार



### जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कलेक्टर ने किया जिला स्तरीय 'प्रोजेक्ट सुरक्षा' अभियान का शुभारंभ कृषि उपज मंडी इटारसी में जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगाए रेडियम टेप

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं जन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी इटारसी परिसर से जिला स्तरीय 'प्रोजेक्ट सुरक्षा' अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद

पंचायत नर्मदापुरम अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौकसे, नगर पालिका इटारसी अध्यक्ष श्री पंकज चौरी, मध्यप्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष श्री पीयूष शर्मा एवं कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा उपस्थित रहे। अभियान के शुभारंभ से पूर्व कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मंडी के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों - कर्मचारियों एवं पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए अभियान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं संभावित लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'प्रोजेक्ट सुरक्षा' का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियों पर

रिफ्लेक्टर (रेडियम) पट्टियां लगाई जाएंगी, जिससे रात्रि के समय उनकी दृश्यता बढ़े और पीछे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही जिले में बड़े स्तर पर सीपीआर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में लोगों को त्वरित प्राथमिक सहायता मिल सके। उन्होंने हेल्मेट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुर्घटनाओं के समय हेल्मेट जीवन रक्षक सिद्ध होता है और इसके उपयोग से मृत्यु की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अभियान के तहत 'हेल्मेट से सुरक्षा' के संदेश के साथ आमजन को जागरूक किया जाएगा। साथ ही चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के उपयोग के प्रति प्रेरित किया जाएगा तथा सभी नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मंडी परिसर में आए विभिन्न ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रेडियम टेप लगाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं। इस दौरान एसडीएम इटारसी श्री निलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नीता कोरी, डीएसपी ट्रैफिक श्री संतोष मिश्रा, उपसंचालक कृषि श्री रविकांत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।

# उपार्जन केंद्रों पर किसानों को न हो किसी भी प्रकार की समस्या

## कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने केसला तहसील का सघन निरीक्षण कर उपार्जन केंद्रों, जनपद एवं विद्यालय व्यवस्थाओं पर दिए व्यापक निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने अनुविभाग इटारसी अंतर्गत केसला तहसील का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गेहूँ उपार्जन केंद्रों, जनपद पंचायत कार्यालय एवं सांदिपनि विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर चल रही खरीदी व्यवस्था, किसानों को उपलब्ध सुविधाओं तथा समुचित प्रबंधन का अवलोकन किया। साथ ही जनपद पंचायत में संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। सांदिपनि विद्यालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं, विद्यालय के निर्माण एवं परिसर का भ्रमण कर अन्य तकनीकी पक्षों का भी जायजा लिया और



संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर एसडीएम श्री निलेश शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ केसला श्रीमती सुमन खातकर सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उपार्जन केंद्रों पर हो किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, एफएक्यू मानक के अनुरूप हो खरीदी : कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने केसला अंतर्गत उपार्जन एवं मीना वेयरहाउस में स्थापित गेहूँ उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं खरीदी प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण



## शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य किया जाए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी विद्यालय निर्धारित समय पर खुलना सुनिश्चित किए जाएं तथा शिक्षक स्कूल समय से कम से कम आधा घंटा पूर्व उपस्थित रहें। उन्होंने निर्देशित किया कि बिना अनुमति के प्रिंसिपल, कोई भी शिक्षक अथवा कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेगा। अनधिकृत अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध निलंबन सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने

कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जिन विद्यालयों में परीक्षा परिणाम कमजोर रहे हैं, वहां विशेष शैक्षणिक गतिविधियां संचालित कर सुधार लाया जाए। उन्होंने विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने, ड्रॉप आउट रोकने तथा बच्चों के सीखने के स्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जिले के शासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक स्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, गणवेश वितरण, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाएं तथा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

की परामर्शदाता श्रीमती रेखा राठौर ने महिला से लगातार संवाद स्थापित किया तथा विश्वासपूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत कर उनके परिवार एवं निवास संबंधी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। कई दिनों के प्रयासों के बाद महिला ने अपने गांव एवं क्षेत्र के बारे में जानकारी देना प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे बिहार राज्य के मधुबनी क्षेत्र के आसपास की निवासी हैं।

महिला के स्वास्थ्य में पूर्ण सुधार होने के बाद वन स्टॉप सेंटर द्वारा उनके सुरक्षित पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस कार्य में जीआरपी विदिशा का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। विभागों के समन्वित प्रयासों से महिला को सुरक्षित रूप से मधुबनी, बिहार भेजा गया। वहां मधुबनी वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से उन्हें उनके गांव सलोनी में उनके परिवार तक पहुंचाया गया। कई दिनों से लापता वृद्ध महिला को सुरक्षित अपने बीच पाकर परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवारजनों ने प्रशासन एवं वन स्टॉप सेंटर की टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिली सहायता ने उनकी उम्मीदों को फिर से जीवित कर दिया।

यह पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि संवेदनशील प्रशासन, मानवीय व्यवहार एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। वन स्टॉप सेंटर की यह पहल समाज के लिए प्रेरणादायक है तथा यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मानवता और सेवा की भावना सबसे बड़ी ताकत होती है।

## जनसहभागिता से जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में बैतूल को मॉडल जिला बनाएं: कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे

बैतूल (निप्र)। पंख कार्यक्रम अंतर्गत दृष्टि योजना के तहत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सभी स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि जिले में पर्यावरण संरक्षण, वन



ऊर्जा, नशा मुक्ति, प्राकृतिक कृषि सहित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन में भी इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अभी भी जिले

में जल संरक्षण एवं संवर्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने पूर्व में किए गए जल संरक्षण कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे आगामी परियोजनाओं के लिए उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने सभी संस्थाओं से बैतूल जिले को जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में मॉडल जिला बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बैतूल जिले के नागरिक सामाजिक

संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत नवांकुर संस्थाओं एवं प्रस्फुटन समितियों से कहा कि नदी पुनर्जीवन के महत्व को देखते हुए रिज टू वेली तकनीक के आधार पर कार्य करें। साथ ही जन अभियान परिषद को नदी पुनर्जीवन के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा स्वैच्छिक संगठनों के सुझाव एवं सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी मानसून से पूर्व ऐसी कम से कम एक पहाड़ी का चिह्नकन करने के निर्देश दिए, जहां हरियाली नहीं है और जहां जनसहभागिता से बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सके। बैठक में माचवा नदी के अकिल प्रवाह को बनाए रखने के संबंध में भी चर्चा की गई तथा इस दिशा में प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने का आग्रह किया गया।

कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्राम सायंगोहन में नमन सेवा संस्था द्वारा प्राकृतिक खेती की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अन्य लोगों से भी वहां जाकर कार्यों का अवलोकन करने का आग्रह किया। उन्होंने जल



## शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य किया जाए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी विद्यालय निर्धारित समय पर खुलना सुनिश्चित किए जाएं तथा शिक्षक स्कूल समय से कम से कम आधा घंटा पूर्व उपस्थित रहें। उन्होंने निर्देशित किया कि बिना अनुमति के प्रिंसिपल, कोई भी शिक्षक अथवा कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेगा। अनधिकृत अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध निलंबन सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने

कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जिन विद्यालयों में परीक्षा परिणाम कमजोर रहे हैं, वहां विशेष शैक्षणिक गतिविधियां संचालित कर सुधार लाया जाए। उन्होंने विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने, ड्रॉप आउट रोकने तथा बच्चों के सीखने के स्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जिले के शासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक स्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, गणवेश वितरण, बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाएं तथा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।



# सोमनाथ

सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।  
लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्ग समाश्रयेत्॥

विरासत के 75 साल

सोमनाथ भारत की अजेय सभ्यता का प्रतीक है। 1000 वर्षों के विनाशकारी प्रहारों के बाद भी, सोमनाथ आज हमारे आत्म-सम्मान और साहस की मिसाल बनकर खड़ा है। 75 वर्ष पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के संकल्प से आधुनिक सोमनाथ का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, आज यह पावन भूमि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उद्घोष कर रही है।



इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बनें

मुख्य गतिविधियां

कलश यात्रा | भजन संध्या | ॐकार मंत्र का जाप  
सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन | सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन

श्री सोमनाथ मंदिर परिसर, प्रभास पाटन | 8 से 11 मई, 2026

“ सोमनाथ आशा का वह गीत है जो हमें सिखाता है कि  
सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। ”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (अध्यक्ष, श्री सोमनाथ ट्रस्ट)



सोमनाथ की दिव्यता एवं भव्यता में दें योगदान और बनें  
गौरवशाली इतिहास का हिस्सा।  
स्कैन करें।